मार्च 2024
खंड - XL | अंक - I

एक्ज़िमिअस: निर्यात लाभ

इस अंक में

- भारत की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को सामने लाना
- भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के व्यापारिक संबंध
- भारत की उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था
- भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच व्यापार तथा निवेश संबंध
- भारत-ओमान संबंधों को बढ़ावा देना

संपादकीय टीम:
श्री डेविड सिनाटे, *मुख्य महाप्रबंधक*
श्री विश्वनाथ जांध्याला, *सहा. महाप्रबंधक*
सुश्री अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*

इंडिया एक्ज़िम बैंक
की तिमाही प्रकाशन

केन्द्र एक भवन, 21 वीं मंज़िल,
विश्व व्यापार केन्द्र संकुल,
कफ़ परेड, मुंबई - 400 005.
फोन: 022 2217 2600
ईमेल: ccg@eximbankindia.in
www.eximbankindia.in
www.eximmitra.in

भारत की ई-कॉमर्स निर्यात क्षमता को सामने लाना

– **जाह्नवी सिंह,** *मुख्य प्रबंधक,*
नेहा रामन, *प्रबंधक*

विशेष रूप से डिजाइन किए गए तौर-तरीकों से कंप्यूटर नेटवर्क के जरिए वस्तुओं या सेवाओं की खरीद-बिक्री के दिए और लिए गए ऑर्डरों की कवायद ई-कॉमर्स की श्रेणी में आती है। वर्ष 2017 से 2022 के दौरान वैश्विक ई-कॉमर्स बिक्री में 16.6% की मजबूत सीएजीआर दर्ज की गई है। यह 2022 में 24.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर के स्तर तक पहुंच चुकी है। बीते कुछ वर्षों में ई-कॉमर्स में वृद्धि के पीछे विशेष रूप से बड़ा कारण उपभोक्ताओं और व्यवसायों द्वारा रिमोट खरीदारी और बिक्री पद्धति को तेजी से अपनाना रहा है।

भारत का ई-कॉमर्स बाजार दुनिया का आठवां सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाले बाजारों में से एक है। भारतीय ई-कॉमर्स बाजार का मूल्य 2020 में 46.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इसके 2023 में 63.2 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। कोविड-19 महामारी के दौरान बिक्री वृद्धि में हुए उतार-चढ़ाव के कारण इस अवधि के दौरान इसमें 11% की सीएजीआर दर्ज की गई।

अंकटाड के हालिया अनुमान से पता चलता है कि वैश्विक ई-कॉमर्स राजस्व में औसतन 21% हिस्सेदारी क्रॉस बॉर्डर बिक्री की है। अर्थात् विभिन्न देशों के बीच होने वाली सीमा पार बिक्री की। इस अनुमान के आधार पर माना जा रहा है कि 2022 में क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स का मूल्य 5.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर के आस-पास रह सकता है। वर्ष 2021 में अंकटाड द्वारा प्रकाशित नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2019 में क्रॉस-बॉर्डर बी2सी ई-कॉमर्स 440 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें 8.9% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की गई। उल्लेखनीय है कि ई-कॉमर्स माध्यम से निर्यात करने वाले शीर्ष 10 देशों ने वर्ष 2019 में कुल क्रॉस बॉर्डर बी2सी ई-कॉमर्स बिक्री में 75% की हिस्सेदारी दर्ज की है। इनमें चीन ने सबसे अधिक क्रॉस बॉर्डर बी2सी ई-कॉमर्स निर्यात किया। वर्ष 2019 के कुल क्रॉस बॉर्डर बी2सी ई-कॉमर्स में इसकी हिस्सेदारी 23.9% (उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार) रही। इसके बाद अन्य में संयुक्त राज्य अमेरिका (20.5% की हिस्सेदारी), यूके (8.6%), हांगकांग (8%) और जापान (5.2%) का स्थान रहा।

जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुल ई-कॉमर्स बिक्री का लगभग एक-चौथाई हिस्सा सीमा पार ट्राज़ैक्शन का रहता है। तदनुसार, 2022 में भारत में क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स का मूल्य 15.8 बिलियन यूएस डॉलर रहने का अनुमान है। यह वैश्विक क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्स के अनुमानित मूल्य का लगभग 0.3% और भारत के कुल निर्यात (वस्तु और सेवाएं मिलाकर) के 2% के आस-पास है। वैसे, मलेशिया और थाईलैंड जैसे देशों की तुलना में यह हिस्सेदारी बहुत कम है। ई-कॉमर्स के कुल निर्यात में मलेशिया की 8% और थाईलैंड की 5% हिस्सेदारी है।

भारत के ई-कॉमर्स निर्यात को बढ़ाने के लिए चुनिंदा रणनीतियां

ई-कॉमर्स निर्यात के लिए जीआई उत्पादों पर फोकस करना

भारत सरकार अग्रणी ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों के सहयोग से ई-कॉमर्स के माध्यम से भौगोलिक उपदर्शन (जीआई) वाले भारतीय उत्पादों को बढ़ावा देने पर विचार कर सकती है। इटली सरकार ने यही तरीका अपनाया हुआ है। उसने संरक्षित उत्पत्ति संकेत (पीडीओ) या संरक्षित भौगोलिक उपदर्शन (पीजीआई) वाले इतालवी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजॉन के साथ एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य पीडीओ या पीजीआई वाले उत्पादों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करना भी है। इस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बेचे जाने वाले पीडीओ या पीजीआई उत्पादों के बारे में अगर कहीं, कभी गलत जानकारी दी जाती है या किसी अन्य अनुचित तरीकों से उनसे संबंधित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो तुरंत इसकी सूचना सरकार के साथ साझा की जाती है। जांच के साथ-साथ उचित कार्रवाई भी की जाती है। इस करार में अमेज़ॉन को नकली उत्पादों को तुरंत हटाने का भी अधिकार है। भारत सरकार इसी तरह के सहयोग पर विचार कर सकती है, जिससे गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर उपभोक्ताओं के भरोसे को मजबूत किया जा सके और ई-कॉमर्स के माध्यम से जीआई टैग वाले उत्पादों की बिक्री और निर्यात को बढ़ाया जा सके।

संभावित बाजारों को चिह्नित करना

एक्ज़िम बैंक के विश्लेषण से संकेत मिलता है कि चिह्नित किए गए बाज़ारों में से, भारत केवल संयुक्त अरब अमीरात के मामले में ही क्रॉस-बार्डर ई-कॉमर्स के लिए आयात का शीर्ष स्रोत है। इसके अलावा 2022 के अपने किसी भी अन्य शीर्ष व्यापारिक निर्यात स्थल, जैसे- संयुक्त राज्य अमेरिका, नीदरलैंड, चीन, सिंगापुर, यूके और जर्मनी में भारत शीर्ष आयात स्रोतों में शामिल नहीं है। यह स्थिति इस बात का संकेत भी है कि ई-कॉमर्स निर्यात के लिए इन बाजारों में पर्याप्त दोहन की संभावना मौजूद है। क्योंकि निर्यात के पारंपरिक तरीकों के तहत भारत की इन बाजारों में पहले से ही पर्याप्त उपस्थिति है।

अधिक देशों को दायरे में लाने के लिए आईटीपीएस का विस्तार करना

इंटरनेशनल ट्रैक्ड पैकेट सर्विस (आईटीपीएस) को भारतीय डाक द्वारा डिजाइन किया गया है। यह सेवा एमएसएमई, छोटे व्यवसायों और व्यापारियों सहित ई-कॉमर्स निर्यातकों की क्रॉस बॉर्डर शिपिंग आवश्यकताओं को पूरा करने और स्थानीय डाकघरों का उपयोग कर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। फिलहाल यह 41 देशों के लिए उपलब्ध है। भारत के कई शीर्ष निर्यात स्थल वर्तमान में आईटीपीएस के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। ऐसे में, भारत आईटीपीएस के तहत बांग्लादेश, सऊदी अरब, यूके जैसे प्रमुख आयातक देशों के साथ सहयोग करने पर विचार कर सकता है। ये सभी देश भी वर्तमान में आईटीपीएस के दायरे से बाहर हैं। इसके अलावा, आईटीपीएस के तहत लिए जाने वाले डाक शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर भी विचार करने की जरूरत है। यह शुल्क प्रथम 50 ग्राम के लिए औसतन लगभग ₹ 341 और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम के लिए औसतन ₹ 32.8 है। समझा जा सकता है कि छोटे निर्यातकों के लिए और उन्हें इस सेवा के उपयोग के लिए हतोत्साहित कर सकती है। चूंकि डाक मार्गों का उपयोग मुख्य रूप से एमएसएमई द्वारा कम मूल्य के निर्यातों के लिए किया जाता है, इसलिए सरकार एमएसएमई निर्यातकों के लिए डाक शुल्क में छूट देने पर विचार कर सकती है। अथवा इस शुल्क को तर्कसंगत बनाने पर विचार कर सकती है।

अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए ओएनडीसी को बढ़ावा देना

भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की व्यवस्था है। यह सुविधा ऐसा नेटवर्क प्रदान करती है, जिससे विभिन्न उद्योगों के स्थानीय डिजिटल कॉमर्स स्टोर्स को किसी भी नेटवर्क-आधरित एप्लिकेशन द्वारा खोजा जा सके, उनसे जुड़ा जा सके। ओएनडीसी आर्किटेक्चर में खरीदार, विक्रेता और लॉजिस्टिक प्रदाता शामिल हैं। ओएनडीसी नेटवर्क प्रोटोकॉल भौगोलिक प्रतिबंधों के बिना संचालित होता है। यानी यह विक्रेता को किसी भी स्थान पर, यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी, खरीदारों को अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदान करने की गुंजाइश देता है। उल्लेखनीय है कि इस नेटवर्क ने जनवरी 2024 में सिंगापुर के साथ अपना पहला सीमा पार ट्रांज़ैक्शन सफलतापूर्वक संचालित किया है। अब यह नेटवर्क अपनी इस पहल को विस्तार देने की दिशा में बढ़ रहा है। ऐसे में, भारत की सीमाओं से परे ओएनडीसी को विस्तार देने के लिए, कुछ प्रमुख सहायक कारकों को भी स्थापित करना महत्त्वपूर्ण होगा। इन कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं- 1) निर्बाध सीमा पार भुगतान निपटान; 2) सुदृढ़ शिकायत निवारण प्रणाली; 3) देश-विशिष्ट दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता; और 4) अंतरराष्ट्रीय ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों के साथ सहयोग।

निर्यात ऋण तक ई-कॉमर्स निर्यातकों की पहुंच बढ़ाना

इंडिया एक्ज़िम बैंक की हितधारकों के साथ हुई चर्चा के अनुसार, प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की अनुपलब्धता ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एक चुनौती मानी जाती है। ई-कॉमर्स व्यवसायियों को वित्तपोषित करना बैंकों को चुनौतीपूर्ण लगा, क्योंकि पुष्ट किए गए ऑर्डर/साख पत्रों की अनुपलब्धता के साथ-साथ खरीदारों की उचित जांच करने में भी चुनौतियां थीं। इसके अलावा, ई-कॉमर्स में निर्यात प्राप्ति की वसूली पर नजर रखना भी बैंकों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। इसके समाधान के लिए, सबसे पहले ई-कॉमर्स निर्यातक की वित्तपोषण आवश्यकता का गहन मूल्यांकन करना महत्वपूर्ण होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रांज़ैक्शन के पारंपरिक तरीके के विपरीत, ई-कॉमर्स निर्यातों में ऑर्डर के समय ही विक्रेताओं को अग्रिम भुगतान मिलने का बंदोबस्त होता है। वित्तपोषण की आवश्यकता को समझने से ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए अनुरूप वित्तपोषण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करने में भी मदद मिलेगी। इस बाबत गौर करने लायक है कि थाईलैंड के निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम थाईलैंड) ने एक अलग वित्तपोषण कार्यक्रम पेश किया भी है। इसे `ई-कॉमर्स फायनैंसिंग लोन' कहते हैं। थाईलैंड निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम थाइलैंड) इसके तहत चुनिंदा ई-कॉमर्स प्लैटफॉर्मों के जरिए क्रय-विक्रय करने वाले व्यवसायों को 10 महीने तक के लिए अल्पकालिक रिवॉल्विंग क्रेडिट (शिपमेंट से पहले और बाद की अवधि सहित) देता है। इसी तर्ज पर, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा भारत में ई-कॉमर्स निर्यातकों की सहायता के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किया जा सकता है।

भुगतान समाधान संबंधी चुनौतियों से निपटना

हितधारकों के साथ इंडिया एक्ज़िम बैंक की चर्चा के अनुसार, भुगतान प्राप्ति और समाधान थर्ड पार्टी ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। भुगतान समाधान से संबंधित मुद्दे मुख्य रूप से ई-कॉमर्स निर्यातों से जुड़े होते हैं। पारंपरिक, थोक और बी2बी निर्यातों के समान नियामक लेंस से इन्हें भी देखा जाता है। इसके अलावा, प्रचलित फेमा नियम बी2सी ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए अनुपालन को अव्यवहार्य बनाते हैं। इन मुद्दों के समाधान के लिए इन्हें उचित रूप से संशोधित करने की जरूरत है। भारत सरकार विक्रेता और निर्यातक की जिम्मेदारियों को सीमांकित करते हुए भारत से ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए अनुकूल नीतिगत बनाने पर भी विचार कर सकती है। इसके अलावा, निर्यातकों ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि ई-बीआरसी और ईडीपीएमएस को बंद करने पर बैंक शुल्क ₹1,500 से ₹ 2,000 के बीच है, जो अधिक है। यह राशि इसलिए अधिक है, क्योंकि भारत से ई-कॉमर्स निर्यातों में बड़ी भागीदारी कम मूल्य के शिपमेंट की होती है। कई बैंक पहले ही ग्राहकों के लिए ई-बीआरसी शुल्क वापस ले चुके हैं। ई-बीआरसी शुल्क पर ऐसी छूट पर अन्य वाणिज्यिक बैंक भी विचार कर सकते हैं।

ई-कॉमर्स निर्यातकों को आरओडीटीईपी का अधिक लाभ पहुंचाना

ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए `निर्यातित उत्पादों पर शुल्क या करों में छूट' (आरओडीटीईपी) योजना के तहत लाभ की उच्च दरों के बारे में भी भारत सरकार विचार कर सकती है। इससे ई-कॉमर्स निर्यातकों की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा। ई-कॉमर्स निर्यातकों को ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन से जुड़ी अतिरिक्त लागतें, जैसे- मुद्रा रूपांतरण (करंसी कन्वर्जन) शुल्क, सेवा शुल्क आदि, वहन करनी पड़ती हैं। निर्यातकों के अनुसार, भुगतान गेटवे द्वारा लगाए शुल्क कुछ मामलों में टांज़ैक्शन मूल्य के 4% तक हो जाते हैं, जो एमएसएमई निर्यातकों के लिए रुकावट हो सकते हैं। इसलिए मुद्रा रूपांतरण लागतों पर अदा किए गए जीएसटी और भुगतान गेटवे पर सेवा शुल्कों को ध्यान में रखते हुए सरकार आरओडीटीईपी के तहत ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए प्रतिपूर्ति की दर बढ़ाने पर विचार कर सकती है।

ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए भुगतान गेटवे के रूप में यूपीआई को बढ़ावा देना

ई-कॉमर्स के क्षेत्र में सक्रिय व्यवसायियों को भुगतान गेटवे से संबंधित कई चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। इनमें बिना किसी स्पष्टीकरण के उपयोगकर्ता खातों को फ्रीज करने या निलंबित करने जैसी चुनौतियां भी शामिल हैं। इससे निर्यातकों को वित्तीय नुकसान हो सकता है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए भारत के लिए जरूरी है कि वह ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए भुगतान गेटवे के रूप में एकीकृत भुगतान इंटरफेस (यूपीआई) को बढ़ावा दे। इसके लिए सहभागी देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ यूपीआई के इंटरलिंकेज को बढ़ाने की दिशा में काम किया जा सकता है। हालांकि यूपीआई के अंतरराष्ट्रीयकरण के मामले में पहले से कुछ प्रगति हुई है। भारत ने सिंगापुर के साथ मिलकर दोनों देशों के बीच अपनी पहली क्रॉस-बॉर्डर रीयलटाइम भुगतान प्रणाली यूपीआई-पेनाउ शुरू की है। इसी तरह, अन्य सहभागी देशों के साथ भी उनकी भुगतान प्रणालियों से यूपीआई का इंटरलिंकेज बढ़ाने की जरूरत है, जिससे अधिक मात्रा में सीमापार ट्रांज़ैक्शन अमल में लाया जा सके। इस मामले में एनपीसीआई जापान, अमेरिका, चीन और भूटान जैसे देशों के साथ अपनी मौजूदा साझेदारी का लाभ उठा सकता है। भारत से ई-कॉमर्स निर्यातों के लिए सीमा पार ट्रांज़ैक्शन की सुविधा हेतु अन्य प्रमुख सहभागी देशों की भुगतान प्रणालियों के साथ नए इंटरलिंकेज भी बना सकता है। ऐसी प्रणालियां भारतीय डिजिटल भुगतान प्रदाताओं के लिए अंतरराष्ट्रीय ट्रांज़ैक्शन की लागत कम कर सकती हैं क्योंकि इससे बिचौलियों की संख्या में कमी आएगी।

आरटीए / एफटीए में ई-कॉमर्स को शामिल करने के लिए पुनःवार्ता

हाल के वर्षों में, मुक्त व्यापार करारों (एफटीए) / क्षेत्रीय व्यापार करारों (आरटीए) में ई-कॉमर्स / डिजिटल व्यापार से संबंधित प्रावधान बढ़ रहे हैं। हालाँकि, भारत के मामले में केवल 7 करार ही ऐसे हैं, जिनमें ई-कॉमर्स व्यापार से संबंधित कुछ प्रावधान हैं। जबकि केवल 2 व्यापार समझौते ऐसे हैं, जिनमें ई-कॉमर्स / डिजिटल व्यापार पर अलग से एक खंड है। ये करार हैं - सिंगापुर के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार और संयुक्त अरब अमीरात के साथ व्यापक आर्थिक साझेदारी करारों। ऐसे में भारत के लिए जरूरी है कि वह अपने मौजूदा व्यापार करारों पर फिर से वार्ता करे और ऐसी ही चल रही अन्य वार्ताओं में भी, ई-कॉमर्स प्रावधानों को शामिल कराए। भारत सीमा शुल्क सरलीकरण और पूर्व-निकासी, स्रोत के स्व-प्रमाणन की अनुमति या एक निश्चित राशि से कम मूल्य वाले उत्पादों के लिए प्रमाणन की छूट जैसी प्रक्रियाओं के उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित कर सकता है। ये कदम विशेष रूप से कम मूल्य के ई-कॉमर्स निर्यात के लिए उपयुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा, भारत अपने एफटीए / आरटीए साझीदार देशों के साथ डिजिटल अर्थव्यवस्था करार भी कर सकता है। इस तरह का एक करार न्यूजीलैंड, सिंगापुर और चिली के बीच हुआ है। ये करार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल पहचान, ओपन सरकारी डेटा सहित अन्य कई क्षेत्रों में सहयोग के लिए हो सकते हैं।

जागरूकता बढ़ाना

देश से कुल निर्यातों में ई-कॉमर्स निर्यात की कम हिस्सेदारी का एक महत्त्वपूर्ण कारण ई-कॉमर्स संभाव्यताओं और निर्यात प्रक्रियाओं के बारे में जागरूकता की कमी भी है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने हाल ही में ट्रेड कनेक्ट पोर्टल शुरू करने की घोषणा की है। इस पोर्टल के जरिए ई-कॉमर्स निर्यात से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है, ताकि इस बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। इसके अलावा, सरकार निर्यातकों को अन्य समर्पित पोर्टलों से भी व्यापार और व्यापार वित्त संबंधी जानकारी का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। इनमें एक्ज़िम बैंक द्वारा विकसित `एक्ज़िम मित्र' पोर्टल भी शामिल है, जो विविध प्रकार की जानकारी, सलाहकारी और सहायता सेवाएं प्रदान करता है। ये भी ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए उपयोगी हो सकती हैं। साथ ही साथ बैंकिंग पेशेवरों के लिए जानकारीप्रद कार्यशालाएं आयोजित करने की भी आवश्यकता है ताकि ई-कॉमर्स निर्यातकों के लिए एडी कोड पत्र समय से जारी करने और बैंकों को दस्तावेज जमा करने संबंधित मुद्दों पर प्रभावी ढंग से ध्यान दिया जा सके। उन्हें हल किया जा सके। ■

भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ के व्यापारिक संबंध

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
कनिष्क चौधरी, *अधिकारी*

भारत के दक्षिणी अफ्रीका के साथ ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। इन संबंधों में वह प्रतिबद्धता भी दिखती है कि इस क्षेत्र के साथ भारत का आर्थिक जुड़ाव आगे और गहरा होना है। भारत और दक्षिण अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ (एसएसीयू) के बीच द्विपक्षीय व्यापार संबंध इस बात का एक प्रमुख प्रमाण है। भारत और एसएसीयू के बीच आर्थिक और व्यापार संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार देखा गया है। यह दोनों क्षेत्रों के बीच गहन पारस्परिक विचार–विमर्श को दर्शाता है। बीते एक दशक में, दोनों पक्षों के बीच व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। एसएसीयू के लिए भारत एक प्रमुख व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान, एसएसीयू देशों के साथ भारत का कुल व्यापार 2013 के 13.7 बिलियन यूएस डॉलर से बढ़कर 2022 में 20.5 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। इसके अलावा, भारत ने 2022 में एसएसीयू को हुए कुल निर्यात में 4.6% की हिस्सेदारी दर्ज की है। जबकि वहां के कुल आयात में 6.9% की आपूर्ति भारत ने की है। ये आंकड़े दोनों पक्षों के बीच परस्पर व्यापार व्यवहार में भारत द्वारा बनाए गए प्रभाव को रेखांकित करता है।

एसएसीयू के साथ भारत का वाणिज्यिक वस्तु व्यापार

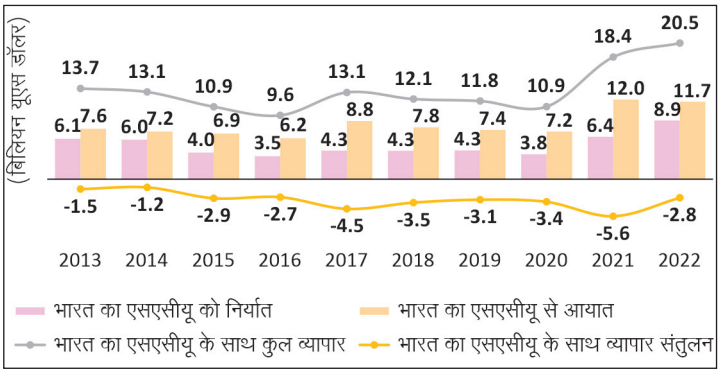

स्रोत : आईटीसी ट्रेड मैप और इंडिया एक्ज़िम बैंक रिसर्च

विविधतापूर्ण निर्यात और प्रमुख क्षेत्र

एसएसीयू को भारत के निर्यात की विशेषता विविधीकरण है। इसके दायरे में परिष्कृत पेट्रोलियम, मोटर वाहन, औषधियां, अनमाउंटेड हीरे, स्मार्टफोन और ऑफ-हाइवे उपयोग वाले डंपर तक शामिल हैं। भारत की ओर से एसएसीयू को किए जाने वाले कुल निर्यात में खनिज ईंधन और तेल की हिस्सेदारी अधिक रही। यह हिस्सेदारी 2022 में 42.7% के करीब रही। वर्ष 2020 (0.6 बिलियन यूएस डॉलर) की तुलना में इसमें 2022 में (3.8 बिलियन यूएस डॉलर) तेज उछाल देखा गया। खनिज ईंधन के अलावा, रेलवे या ट्रामवे को छोड़कर अन्य वाहनों तथा फार्मासूटिकल उत्पादों ने निर्यात में प्रमुख हिस्सेदारी दिखाई। यह कुल निर्यात के 25% से अधिक रही। रेलवे या ट्रामवे को छोड़कर अन्य वाहनों का निर्यात 2020 में जहां 0.6 बिलियन यूएस डॉलर का रहा, वहीं 2022 में यह बढ़कर 1.6 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। जबकि फार्मासूटिकल उत्पादों के निर्यात में मामूली गिरावट (2020 के 0.8 बिलियन यूएस डॉलर से 2022 में 0.7 बिलियन यूएस डॉलर तक) देखी गई। एसएसीयू को भारत से निर्यात की जाने वाली अन्य प्रमुख वस्तुओं में मशीनरी और यांत्रिक उपकरण, विद्युत मशीनरी तथा उपकरण शामिल रहे। साथ ही कीमती धातुएं एवं रत्न तथा प्लास्टिक और इससे बना सामान भी शामिल रहा। फार्मास्यूटिकल उत्पाद भारत से एसएसीयू को निर्यात किए जानेवाली तीसरे सबसे बड़े उत्पाद हैं। इनके निर्यातों में मामूली गिरावट (वर्ष 2022 में एसएसीयू के कुल फार्मासूटिकल उत्पादों के वैश्विक आयात का 22.2%) दर्ज करने के बावजूद, फार्मासूटिकल उत्पादों का महत्त्व कम नहीं हुआ है। बल्कि इसमें उल्लेखनीय वृद्धि ही देखी गई है। इस मामले में औषधीय सामग्री भारत के निर्यात पोर्टफोलियो में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इनमें उपचारात्मक या रोग निरोधक उपयोग (एचएस-3004) के लिए मिश्रित या अमिश्रित उत्पाद शामिल हैं। एसएसीयू को भारत के फार्मासूटिकल्स निर्यात में यह औषधीय सामग्री प्रमुख उत्पाद के रूप में उभरी है।

एसएसीयू में भारत का सबसे बड़ा आयातक दक्षिण अफ्रीका है। वर्ष 2022 में इस क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 93.4% हिस्सा यहीं गया है। भारत के खनिज ईंधन, तेल और उसके उत्पादों, वाहनों, जहाजों, नौकाओं तथा तैरने वाली ऐसी ही अन्य चीजों के निर्यात के लिए दक्षिण अफ्रीका एसएसीयू और अफ्रीका के प्रमुख बाजारों में से एक है। नामीबिया एसएसीयू के भीतर भारत के लिए दूसरा बड़ा आयातक है। एसएसीयू को भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 3.7% है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में इस देश को भारत का निर्यात मामूली रूप से बढ़ा है। नामीबिया को भारत के निर्यात में मुख्य रूप से खनिज ईंधन और तेल, फार्मासूटिकल उत्पाद, एल्यूमीनियम और उससे बनी चीजें तथा अनाज शामिल हैं। बोत्सवाना एसएसीयू में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है। वर्ष 2022 में एसएसीयू को भारत के कुल निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2.5% रही है। यहां के लिए भारत के प्रमुख निर्यातों में कीमती मोती और रत्न तथा फार्मासूटिकल उत्पाद शामिल रहे हैं।

पारस्परिक आयात व्यवहार और प्रमुख वस्तुएं

एसएसीयू से भारत को होने वाले आयात में मुख्य रूप से कच्ची प्राथमिक या अर्ध-प्रसंस्कृत वस्तुएं शामिल हैं। वहां से होने वाले उल्लेखनीय आयातों में मोती, कीमती रत्न, धातु और खनिज ईंधन व तेल शामिल हैं। वर्ष 2022 में इस क्षेत्र से भारत के आयात में 75% से अधिक की हिस्सेदारी सामूहिक रूप से इन्हीं की रही। मोती, कीमती रत्न और धातु की श्रेणी के तहत भारत द्वारा इस क्षेत्र से मुख्यतः सोना (एचएस–7108) आयात किया गया। सोने के आयात का कुल मूल्य 3.3 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इसके बाद 1.5 बिलियन यूएस डॉलर मूल्य का हीरा (एचएस–7102) आयात किया गया। जबकि खनिज ईंधन, तेल और आसवन श्रेणी के उत्पादों के तहत, 2022 के दौरान सबसे अधिक आयात कोयले (एचएस-2701) का हुआ। कोयला आयात का मूल्य करीब 3.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इसके बाद 17.7 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य का कच्चा पेट्रोलियम (एचएस-2709) और 12.3 मिलियन यूएस डॉलर मूल्य से पेट्रोलियम जेली (एचएस-2712) का आयात हुआ। तांबा और तांबे की वस्तुएं इस क्षेत्र से भारत

के आयातों की तीसरी सबसे बड़ी वस्तुएं हैं। वर्ष 2022 के दौरान भारत के तांबे के वैश्विक आयात में एसएसीयू का योगदान 55% रहा है। जबकि भारत के लिए लकड़ी की लुगदी या अन्य रेशेदार सेल्युलोसिक सामग्री के वैश्विक आयात में इस क्षेत्र की हिस्सेदारी 35.5% रही। यह क्षेत्र भारत के लिए कच्चे सोने (एचएस-7108) और हीरे (एचएस-7102) के आयात का भी एक प्रमुख स्रोत है।

दक्षिण अफ्रीका भारत के आयात का सबसे बड़ा स्रोत है। वह भारत को कोयला, कच्चा सोना, गैर-औद्योगिक हीरे, तांबा, मैगनीज अयस्क और कन्सेंट्रेट्स जैसी वस्तुओं की आपूर्ति करता है। एसएसीयू के साथ-साथ अफ्रीका से भी भारत के लिए आयातित मोतियों और कीमती रत्नों का सबसे बड़ा स्रोत दक्षिण अफ्रीका ही है।

व्यापार घाटे की चुनौतियां

व्यापार के परिमाण में मजबूत वृद्धि के बावजूद, भारत को 2022 में एसएसीयू के साथ भारत का व्यापार 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। इस घाटे के कारकों में मोती, कीमती रत्न, धातु, तांबा और तांबे की वस्तुएं, अयस्क, स्लैग व भस्म, लकड़ी की लुगदी, जहाज, नौकाएं, तैरती संरचनाएं, खनिज ईंधन और तेल जैसी वस्तुएं शामिल रहीं। वर्ष 2022 के दौरान इस व्यापार में सबसे अधिक दक्षिण अफ्रीका (2.9 बिलियन यूएस डॉलर) और बोत्सवाना (250 मिलियन यूएस डॉलर) का घाटा रहा। जैसा पहले उल्लेख किया गया, दक्षिण अफ्रीका एसएसीयू में भारत का प्रमुख सहभागी है। एसएसीयू को किए गए भारत के कुल निर्यात का 93.4% दक्षिण अफ्रीका को ही जाता है। जबकि इस क्षेत्र से भारत का 95.7% आयात दक्षिण अफ्रीका से ही होता है।

सेवा क्षेत्र का योगदान

भारत का एसएसीयू के साथ द्विपक्षीय सेवा व्यापार

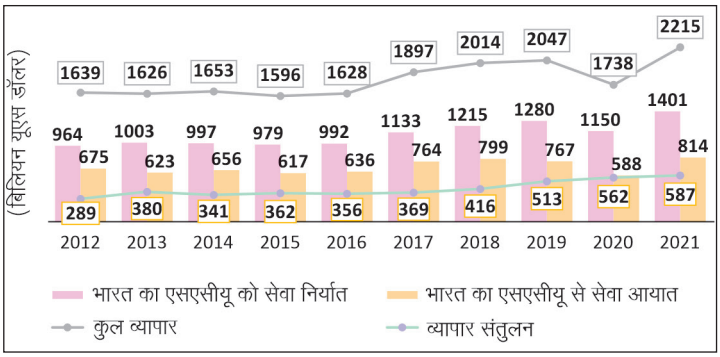

स्रोत : डब्ल्यूटीओ – ओईसीडी सेवाओं में अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन ईबीओपीएस – 2010

वस्तु के व्यापार के अलावा, सेवा क्षेत्र भारत-एसएसीयू संबंधों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वर्ष 2021 में, एसएसीयू को भारत का सेवा निर्यात 1.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच गया। यह 2012 के बाद से 4.6% की सीएजीआर को दर्शाता है। भारत के सेवा निर्यात में भी दक्षिण अफ्रीका ही प्रमुख प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है। एसएसीयू को 2021 में भारत से हुए कुल सेवा निर्यात का 88.4% हिस्सा दक्षिण अफ्रीका ने ही प्राप्त किया। दक्षिण अफ्रीका में भारत का सेवा निर्यात 1.2 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इसमें मुख्य रूप से दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं (65.7%), अन्य व्यावसायिक सेवाएं (18.5%) तथा परिवहन सेवाएं (9.6%) शामिल रहीं।

एसएसीयू से भारत का सेवा आयात 2012 में 675 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह 2021 तक बढ़कर 814 मिलियन यूएस डॉलर हो गया। इस तरह यह 2.3% की एएजीआर से बढ़ा है। एसएसीयू से 2021 में भारत के सेवा-आयात में 92.4% योगदान दक्षिण अफ्रीका का रहा। मूल्य के लिहाज से 2021 में दक्षिण अफ्रीका से भारत का सेवाओं का आयात 752 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें मुख्य रूप से परिवहन और यात्रा सेवाएं (29.7% प्रत्येक), दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं (8.4%) और अन्य व्यावसायिक सेवाएं (19.8%) शामिल रहीं।

दक्षिण अफ्रीका के अलावा बोत्सवाना और नामीबिया सेवाओं के लिए प्रमुख साझेदार के रूप में सामने आए हैं। बोत्सवाना को भारत का सेवा निर्यात 48 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें मुख्य रूप से परिवहन सेवाएं (68.8%) शामिल रहीं। इसके बाद दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं (18.8%) का स्थान रहा। दूसरी ओर, बोत्सवाना से भारत का सेवा आयात 2021 में 15 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें मुख्य रूप से यात्रा सेवाएं शामिल रहीं। नामीबिया के साथ, भारत का सेवा निर्यात 54 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें मुख्य रूप से दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं (37%), अन्य व्यावसायिक सेवाएं (38.9%) शामिल रहीं। जबकि नामीबिया से भारत का सेवा आयात 2021 में 30 मिलियन यूएस डॉलर का रहा। इसमें मुख्य रूप से यात्रा सेवाएं (60%) और परिवहन सेवाएं (16.7%) शामिल रहीं।

विशिष्ट एसएसीयू देशों में सेवा क्षेत्र के योगदान का विस्तृत ब्यौरा देखें तो, दक्षिण अफ्रीका, नामीबिया, लेसोथो, एस्वातिनी और बोत्सवाना के साथ भारत के सेवा निर्यात–आयात की विविधतापूर्ण प्रकृति रेखांकित होती है। हालाँकि, दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाओं, व्यावसायिक सेवाओं, परिवहन सेवाओं तथा यात्रा सेवाओं ने सभी देशों में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए समग्र आर्थिक साझेदारी में योगदान दिया है।

निष्कर्ष और भावी सहयोग

एसएसीयू के साथ भारत के व्यापार संबंधों में गतिशील और उभरती साझेदारी परिलक्षित होती है। इन संबंधों में बढ़ते व्यापार परिमाण, विविधतापूर्ण निर्यात और चुनौतियों पर काबू पाने की प्रतिबद्धता है। हालिया घटनाक्रमों से भारत और एसएसीयू सदस्य देशों के बीच तरजीही व्यापार समझौता (पीटीए) स्थापित करने के नए प्रयास का संकेत भी मिलता है। यह इस क्षेत्र में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए साझा दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बीच, दोनों पक्षों ने वर्चुअल बैठकों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। यह सहभागिता व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के रणनीतिक इरादे का संकेत देती है।

नामीबिया में भारत के उच्चायुक्त श्री प्रशांत अग्रवाल ने चुनौतीपूर्ण आर्थिक समय के दौरान बढ़े हुए व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों के संभावित लाभों पर जोर दिया है। विशेष रूप से, नामीबिया सहित दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र की अर्थव्यवस्थाओं को भारत के साथ बढ़ते सहयोग से महत्त्वपूर्ण लाभ होगा। भारत ने अपनी प्रतिक्रिया में, नामीबिया में कृषि, सिंचाई, नवीकरणीय ऊर्जा, आईसीटी, फार्मासूटिकल्स और चिकित्सा आपूर्ति सहित विभिन्न क्षेत्रों में विनिर्माण और उद्योग का सहयोग करने के लिए पूर्ण प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। चूंकि भारत प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग और निवेश के अवसरों की तलाश जारी रखे हुए है, लिहाजा ये सुनिश्चित है कि आने वाले समय में अधिक एकीकृत और पारस्परिक रूप से लाभप्रद भारत-एसएसीयू आर्थिक साझेदारी होने वाली है। ■

भारत की उभरती अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था

– **राहुल मजूमदार,** *उप महाप्रबंधक*
साक्षी गर्ग, *उप प्रबंधक*

वैश्विक अंतरिक्ष बाजार 2010 में 280 बिलियन यूएस डॉलर का था। यह 2022 में बढ़कर लगभग 447 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया है। अब 2030 तक इसके बढ़कर 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। अंतरिक्ष एजेंसियों वाले देशों की संख्या भी 70 से बढ़कर 100 होने की संभावना है। अंतरिक्ष क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियां भी 600 से बढ़कर 1000 से अधिक होने वाली हैं। जबकि 2022-2030 की अवधि में उपग्रह प्रक्षेपण 145 से बढ़कर 200 की संख्या को पार कर सकते हैं।[1]

विश्व स्तर पर, अंतरिक्ष उद्योग में नवीन प्रौद्योगिकियों, सीमा पार सहयोग और नए व्यापार मॉडल की एक तरह से लहर है। यह बदलाव तकनीकी प्रगति जैसे कि पुनःउपयोग वाली प्रौद्योगिकियों, एवियोनिक्स के न्यूनीकरण और उपग्रह सेवाओं की बढ़ती मांग से प्रेरित है। इससे बड़ी संख्या में छोटे उपग्रहों की तैनाती हो रही है। अंतरिक्ष से संचार, नेविगेशन और अन्य सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया में बदलाव आ रहा है।

भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम दुनियाभर में सर्वाधिक किफायती कार्यक्रमों में से एक है। वर्तमान में इसका मूल्य लगभग 8.4 बिलियन यूएस डॉलर है, जो वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था का लगभग 2% है। भारत ने अपने चंद्र अभियान `चंद्रयान'से, उपग्रहों का निर्माण करके, विदेशी उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित कर दुनियाभर में साख अर्जित की है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) द्वारा तैयार की गई दशकीय परिकल्पना और रणनीति के अनुसार, इसरो और अन्य हितधारकों के सहयोग से 2033 तक भारत के अंतरिक्ष उद्योग के बढ़कर 44 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है। वैश्विक हिस्सेदारी के लिहाज से तब यह लगभग 8% हो सकता है।

मूल्य शृंखला के डाउनस्ट्रीम खंड में डेटा और उपग्रह सेवाएं, पृथ्वी पर्यवेक्षण (ईओ) और डेटा उत्पाद तथा उपयोगकर्ता उपकरण जैसे- जीएनएसएस डिवाइस एवं चिपसेट, टीवी की डिशें, रेडियो रिसीवर इत्यादि शामिल हैं। इनके बारे में अनुमान के मुताबिक इनका बाजार 2030 तक 32.1 बिलियन यूएस डॉलर उच्चतम स्तर तक पहुंच सकता है। टेलीविजन से लेकर मोबाइल कनेक्टिविटी तथा कृषि और आपदा प्रबंधन के लिए रिमोट सेंसिंग तक, अंतरिक्ष संपत्तियों का विस्तार कई प्रकार से लाभकारी साबित हो रहा है फिर चाहे सामाजिक लाभ या राजस्व पैदा करने वाले हो। इस कारण अतिरिक्त अंतरिक्ष संपत्तियों की मांग लगातार बढ़ी है।

उपग्रहों और प्रक्षेपण यानों के डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और संचालन से संबंधित गतिविधियां अपस्ट्रीम खंड में आतीं हैं। प्रोपल्शन सिस्टम्स, गाइडेंस, नेविगेशन, पेलोड, एवियोनिक्स, कंट्रोल सिस्टम्स, बिजली और थर्मल सिस्टम्स तथा संरचनात्मक तत्त्वों की प्राप्ति पर काम करने वाले संगठन सभी अपस्ट्रीम उप-खंड का हिस्सा हैं। भारत में 2033 तक अपस्ट्रीम खंड का बाजार 9.4 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकता है। जबकि जमीनी परिचालन सहित मिडस्ट्रीम खंड के बाजार का आकार 2.5 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है।

भारत में डाउनस्ट्रीम बाजार में निजी क्षेत्र का योगदान है। जबकि अपस्ट्रीम क्षेत्र में सरकार की प्रमुख उपस्थिति है। अनुप्रयोग और उद्देश्य पर ध्यान न दें तो अब तक, इस क्षेत्र के लिए मुद्रीकरण और राजस्व सृजन काफी हद तक डाउनस्ट्रीम एप्लीकेशंस द्वारा ही हुआ है। उपग्रहों के लघुकरण, लॉन्च लागत में कमी और सक्षम प्रौद्योगिकियों, जैसे- क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई / एमएल, 3-डी प्रिंटिंग इत्यादि में प्रगति के साथ डाउनस्ट्रीम एप्लिकेशंस ही उपयोगकर्ता की मांगों को पूरा करने की संभावना बढ़ाती हैं। इसके साथ ही, रिमोट सेंसिंग, संचार और नेविगेशन के लिए क्षेत्रीय विकल्पों के साथ प्रतिस्पर्धा से समग्र पेशकश और व्यवसाय मॉडल पर प्रभाव पड़ने की अनुमान भी है।

भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र के विभिन्न खंडों में अनुमानित वृद्धि

खंड	बाजार का आकार (बिलियन यूएस डॉलर)	2033 का लक्ष्य (बिलियन यूएस डॉलर)	सीएजीआर (2022-33)
उपग्रह संचार (सैटकॉम)	4.19	14.8	12
नेविगेशन	2.28	9.3	14
पृथ्वी पर्यवेक्षण (ईओ)	0.52	8.0	28
उपग्रह निर्माण	0.42	4.6	24
प्रक्षेपण खंड	0.72	3.5	15
जमीनी नेटवर्क	0.14	2.5	30
इन-ऑरबिट अर्थव्यवस्था और अंतरिक्ष अन्वेषण	0.13	1.0	20
अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता	0.001	0.3	68

स्रोत : इन-स्पेस

सैटकॉम: भारत का संचार बाजार काफी परिपक्व हो गया है। जमीन, समुद्र और वायु क्षेत्र में सेवा देने के लिए कुछ प्रमुख निजी कंपनियां अपने स्वयं के उपग्रहों का प्रक्षेपण कर रही हैं। व्यावसायिक उपयोग से जुड़े मामलों के लिए मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स (एमईओ) और लो अर्थ ऑर्बिट्स (एलईओ) को पारंपरिक जियोसिंक्रोनस इक्वेटोरियल ऑर्बिट्स (जीईओ) रास्ता दे रहे हैं। जिससे कि विलंबता को घटाया जा सके। इस खंड में उभर रहे रुझानों में मुख्य रूप से उपग्रह आईओटी, 5जी पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करने वाले उपग्रह, बहुत उच्च थ्रूपुट उपग्रह और एलईओ उपग्रह शामिल है।

ईओ: भारत की ईओ क्षमताएं पिछले कुछ वर्षों में बढ़ी हैं। इससे कृषि और मत्स्य पालन विकास, आपदा प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण और अन्वेषण जैसे महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में रिमोट सेंसिंग डेटा और

[1] मैकिन्से एंड कंपनी

एप्लीकेशंस का उपयोग संभव हो पाया है। इसरो `अंतरिक्ष एवं प्रमुख आपदाओं के अंतरराष्ट्रीय चार्टर' का सदस्य भी है। इस रूप में यह संगठन अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और सक्षम निकायों के साथ महत्त्वपूर्ण उपयोग-मामलों जैसे आपदा प्रबंधन, मौसम निगरानी आदि से संबंधित उपग्रह से मिले चित्र आदि भी साझा करता है।

पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग सेवाएं (पीएनटी): जीपीएस आधारित और अब भारत के `नाविक' जैसी क्षेत्रीय प्रणालियों पीएनटी सेवाओं में गिना जाता है। ये अब रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण संपत्ति मानी जाने लगी हैं। इनका उपयोग कई प्रकार के एप्लीकेशनों में होता है। ये एप्लीकेशन परिवहन, संचार और रक्षा जैसे क्षेत्रों में काम आते हैं। भारत में उपग्रह-आधारित पीएनटी सेवाओं के बाजार में तेजी आने वाली है। कॉमर्शियल नेविगेशन में मूल्य सृजन, ड्रोन गाइडेंस और टोल संग्रह जैसे उभरते उपयोग-मामले तथा शिपिंग, वित्तीय ट्रांज़ैक्शन, हवाई अड्डे के संचालन एवं आपूर्ति शृंखला प्रबंधन से जुड़े संभावित एप्लीकेशन बाजार की इस तेजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं।

अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित किए गए खंडवार क्षेत्र

पृथ्वी पर्यवेक्षण	कृषि, वानिकी और महासागर, आपदा और आपातकालीन प्रबंधन, बीमा और वित्त, परिवहन, बुनियादी ढांचा, उपभोक्ता समाधान, ऊर्जा और खनन, जलवायु सेवा और पर्यावरण निगरानी।
पोजीशन नेविगेशन टाइमिंग	कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन, आपदा और आपातकालीन प्रबंधन, परिवहन, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, उपभोक्ता समाधान, ऊर्जा और खनन।
संचार	आपदा एवं आपातकाल, बैंकिंग एवं वित्त, मीडिया एवं मनोरंजन, परिवहन, उपभोक्ता समाधान, ऊर्जा एवं खनन।
जमीनी नेटवर्क	ईओ से जुड़े समाधान, पीएनटी, और संचार का जमीनी नेटवर्क।
घरेलू उपग्रह निर्माण मांग	छोटे उपग्रहों के निर्माण का वैश्विक केंद्र।
घरेलू मांग के हिसाब से प्रक्षेपण सेवाएं	छोटे प्रक्षेपण यानों और प्रक्षेपण सेवाओं के लिए वैश्विक केंद्र।
अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता	वैश्विक मिशन सहयोग सेवाएं और निगरानी।

स्रोत : इन-स्पेस

भारत का अंतरिक्ष उद्योग वर्तमान में मुख्य रूप से घरेलू बाजार की मांग ही पूरा कर रहा है। इस क्षेत्र से निर्यात अभी 0.3 बिलियन यूएस डॉलर है। यह 2033 तक बढ़कर 11 बिलियन यूएस डॉलर का हो सकता है। यह वृद्धि 2022-2033 के दौरान 38% की अपेक्षित सीएजीआर है। इस संबंध में भारत का लक्ष्य भारत-प्रशांत क्षेत्र में वर्टिकल मूल्य शृंखलाओं में अपनी उपस्थिति बढ़ाना है।

अंतरिक्ष क्षेत्र को खोलना

निजी क्षेत्र की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए, सरकार ने भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) बनाया है। यह अंतरिक्ष विभाग के तहत सिंगल विंडो जैसी स्वतंत्र, नोडल एजेंसी है। इसका मुख्य कार्य अंतरिक्ष क्षेत्र में गैर-सरकारी संस्थाओं की भूमिका को बढ़ावा और विस्तार देना, उन्हें सहायता प्रदान करना और समान अवसर उपलब्ध कराना है। यह एजेंसी निजी कंपनियों को इसरो की सुविधाओं के उपयोग के लिए अधिकृत करती है। साथ ही भारतीय उपग्रह प्रणालियों के विकास और निजी क्षेत्र द्वारा विकसित रॉकेट अथवा यानों के प्रक्षेपण के लिए भी उन्हें अधिकृत करती है।

इसके अलावा, भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 भी जारी की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए विशिष्ट भूमिका निभाने हेतु नई सरकारी संस्थाएं बनाकर निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच परस्पर सहजीवी संबंध स्थापित करना है। इससे इसरो की भूमिका उन्नत प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और विकास तथा दीर्घकालिक परियोजनाओं के विकास पर अधिक केंद्रित हो सकेगी।

यही नहीं, भारत सरकार ने फरवरी-2024 में अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए एफडीआई नियमों में ढील भी दी है। तदनुसार-

- स्वचालित मार्ग के तहत उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और यूजर सेगमेंट के लिए घटकों और प्रणालियों / उप-प्रणालियों के विनिर्माण में 100% तक एफडीआई की अनुमति है।
- स्वचालित मार्ग के तहत उपग्रहों के विनिर्माण और संचालन, सैटेलाइट डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट में 74% तक एफडीआई की अनुमति है।
- स्वचालित मार्ग के तहत प्रक्षेपण वाहनों और संबंधित प्रणालियों या उप-प्रणालियों तथा अंतरिक्ष यानों के प्रक्षेपण और उन्हें वापस लाने के लिए स्पेसपोर्ट के निर्माण में 49% तक एफडीआई की अनुमति है।

भारतीय अंतरिक्ष उद्योग की वैश्विक बाजार में केवल 2% हिस्सेदारी है। हालांकि इसरो का लक्ष्य इस क्षेत्र की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी को 10% तक बढ़ाना है। जिससे कि भारत की अंतरिक्ष गतिविधियों को और बढ़ाया जा सके। साथ ही अन्य अंतरिक्ष-क्षेत्रीय देशों के साथ प्रतिस्पर्धा की जा सके। चूंकि इसरो के पास उपग्रहों और प्रक्षेपण यानी का बड़ी हिस्सेदारी मौजूद है। इसे देखते हुए भारतीय निजी क्षेत्र ने भी इन गतिविधियों में कदम बढ़ाए हैं।

भारत में 2033 तक अंतरिक्ष क्षेत्र में 22 बिलियन यूएस डॉलर के निवेश का अनुमान लगाया गया है। निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए द्वार खोलने के साथ ही एक अनुकूल वातावरण बनाया जा रहा है। उसे बढ़ावा दिया जा रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि आने वाले दशकों में भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र विकास के नए प्रतिमान स्थापित करेगा। ■

भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र में वृद्धि के मुख्य घटक

प्रक्षेपण क्षमता और कम प्रक्षेपण लागत	कम लागत वाले मिशन	एफडीआई मानदंडों में ढील	उपग्रह सेवाओं की बढ़ती मांग	वैश्विक स्तर पर उभरते क्षेत्र	भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023
• इसरो द्वारा प्रक्षेपण सेवाएं अपेक्षाकृत कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं।	• काफी कम लागत में अंतरिक्ष यान विकसित करने और प्रक्षेपित करने का भारत का अच्छा रिकॉर्ड है।	• अंतरिक्ष क्षेत्र में 100% तक एफडीआई की अनुमति दी गई है। इससे विदेशी कंपनियां विनिर्माण सुविधाएं स्थापित कर सकेंगी।	• उपग्रह संचार और अनुप्रयोग के अन्य क्षेत्रों में नवाचारों के साथ, अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं की मांग बढ़ रही है।	• अंतरिक्ष पर्यटन और अंतरिक्ष संसाधनों की वाणिज्यिक पुनर्प्राप्ति जैसे क्षेत्रों में अवसर।	• यह अंतरिक्ष गतिविधियों वाले सभी क्षेत्रों में निजी संस्थाओं की पूर्ण भागीदारी को सक्षम बनाती है।

भारत और यूरेशियन आर्थिक संघ के बीच व्यापार तथा निवेश संबंध

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
श्रीजिता नंदी, *उप प्रबंधक*

आर्थिक एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए रूस, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और ताज़िकिस्तान को शामिल करते हुए वर्ष 2000 में एक आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई थी। इसे यूरेशियन आर्थिक समुदाय (ईयूआरएसेक) कहा जाता था। हालांकि वर्ष 2014 में इस संगठन के सदस्य देशों के बीच एक समझौता हुआ। उसके जरिए ईयूआरएसेक को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद, 1 जनवरी, 2015 को यूरेशियन आर्थिक संघ (ईएईयू) का शुभारंभ किया गया। ईएईयू के वर्तमान सदस्यों में आर्मेनिया, बेलारूस, कज़ाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और रूस शामिल हैं। ईएईयू 20,229,248 वर्ग किलोमीटर^2 क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी अनुमानित संचयी जनसंख्या 182.2 मिलियन है। इसके जमीनी क्षेत्रफल में 84% हिस्सा रूस का है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक अप्रैल-2023 के अनुसार, यूरेशियन आर्थिक संघ क्षेत्र ने 2022 में लगभग 2.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर की नॉमिनल जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दर्ज की। यह विश्व की जीडीपी का 2.4% हिस्सा है। रूस, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इस नाते 2022 में इस क्षेत्र की नॉमिनल जीडीपी में 87.7% और कुल जनसंख्या का 79.1% हिस्सेदारी उसी की रही।

यूरेशियन आर्थिक संघ का विदेश व्यापार

ईएईयू का कुल वाणिज्यिक वस्तु व्यापार 2013 में 1.1 ट्रिलियन यूएस डॉलर का था। यह 2022 में घटकर 963.6 बिलियन यूएस डॉलर का रह गया। इसका मुख्य कारण आयात में कमी है। ईएईयू देशों में, रूस अग्रणी व्यापारिक राष्ट्र है। इस क्षेत्र के कुल व्यापार में 2022 में रूस की हिस्सेदारी 81% रही। इसके बाद कज़ाकिस्तान का स्थान है। कुल व्यापार में उसका 14.0% हिस्सा रहा। फिर 2.5% हिस्सेदारी के साथ बेलारूस का स्थान रहा। साल 2022 में आर्मेनिया और किर्गिज़स्तान का कुल व्यापार में क्रमशः 1.4% और 1.2% हिस्सा रहा।

ईएईयू का वाणिज्यिक वस्तु निर्यात 2021 में 597.1 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। यह 2022 में बढ़कर 683.2 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इस वृद्धि में मुख्य रूप से कच्चे तेल के बढ़े निर्यात की भूमिका रही। ईएईयू का निर्यात प्राथमिक वस्तुओं और प्राकृतिक संसाधन-आधारित विनिर्माण की ओर अधिक झुका हुआ है। ईएईयू खनिज ईंधन और तेल उत्पादन में विशेषज्ञता रखता है। परिणामस्वरूप, 2022 में इसके कुल निर्यात में 65% हिस्सेदारी खनिज ईंधन की रही है। अन्य प्रमुख निर्यातों में लोहा और इस्पात (विशेष रूप से आधे–तैयार उत्पाद) शामिल हैं, जिनका कुल निर्यात में हिस्सा 4.5% है। इसके बाद कीमती धातुएं (सोना, प्लैटिनम, हीरे और चांदी), उर्वरक और एल्युमीनियम आदि शामिल हैं।

ईएईयू का आयात 2021 में 387.6 बिलियन यूएस डॉलर का था। यह 2022 402.8 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। क्षेत्र का आयात पूंजी गहन बना हुआ है। इस क्षेत्र के आयातों की संरचना में यह स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होता है। इसमें मशीनरी और यांत्रिक उपकरणों जैसे- स्वचालित डेटा–प्रॉसेसिंग मशीन, संयंत्रों या प्रयोगशालाओं के लिए मशीनरी, पाइपों के लिए उपकरण; विद्युत मशीनरी तथा उपकरण जैसे- टेलीफोन, इलेक्ट्रिक हीटर, पैनल व मॉनिटर एवं वाहन, वाहन के पुर्जे और सहायक उपकरण, आदि के आयात की प्रधानता है।

इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति और अधिकांश देशों के साथ जमीनी–सीमा से घिरे होने के कारण ईएईयू का प्रमुख पारंपरिक व्यापारिक साझेदार पड़ोसी चीन रहा है। रूस इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है। इस नाते शेष चार ईएईयू देशों के लिए यह एक अन्य प्रमुख व्यापारिक साझेदार भी है। वर्ष 2022 में ईएईयू के कुल निर्यात का 36% हिस्सा ईयू (यूरोपीय संघ) को गया। तुर्की, इटली, जर्मनी, नीदरलैंड और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश ईएईयू देशों के प्रमुख व्यापारिक साझेदारों में शामिल हैं। अलग-अलग देशों के हिसाब से देखें तो 2022 में ईएईयू के कुल निर्यात में 19% हिस्सेदारी चीन की रही। इसके बाद तुर्की (2022 में कुल निर्यात का 9.4%) और इटली (6.5%) का स्थान रहा। वर्ष 2022 में भारत चौथा सबसे बड़ा आयातक रहा। 2022 में ईएईयू के कुल निर्यात में भारत की 6.3% हिस्सेदारी रही (2021 में 1.8 हिस्से के साथ 15वां स्थान)।

इसी तरह, 2022 में ईएईयू के कुल आयात में भी 26.2% हिस्सेदारी ईयू की रही। जबकि 2019 में यह हिस्सेदारी 29.8% थी। निर्यात की तरह ही आयात के मामले में भी चीन ईएईयू देशों का प्रमुख स्रोत रहा। 2022 में ईएईयू के आयात में उसकी 34.2% हिस्सेदारी रही। उसके बाद रूस, जर्मनी और तुर्की का स्थान रहा। हालांकि क्षेत्र के कुल आयात में रूस की हिस्सेदारी में गिरावट देखी गई । लेकिन वह अब भी ऊर्जा और विनिर्मित उत्पादों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत 2022 में ईएईयू के कुल आयात में 1.4% की हिस्सेदारी के साथ 16वां सबसे बड़ा आयात आपूर्तिकर्ता रहा।

भारत–ईएईयू द्विपक्षीय वाणिज्यिक वस्तु व्यापार संबंध

यूरेशियाई आर्थिक संघ भारत के लिए काफी रणनीतिक महत्त्व का क्षेत्र है। इसका कारण है इस क्षेत्र की अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, इसकी खनिज और हाइड्रोकार्बन संपदा तथा भूमि और समुद्री मार्गों के माध्यम से इस क्षेत्र से गुजरते हुए कई व्यापारिक गलियारों के विकास की संभावनाएं। यह क्षेत्र भारत के `विस्तारित पड़ोस' का हिस्सा होने के नाते, भारतीय विदेश नीति में भी महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के वैश्विक निर्यात में ईएईयू को निर्यातों की हिस्सेदारी 0.8% रही। वही 2022 में भारत के वैश्विक आयातों में इन देशों से आयातों की हिस्सेदारी 4.8% रही। औसतन, इस क्षेत्र को भारत से निर्यात 2022 में 3.5 बिलियन यूएस डॉलर रहा। यह 2021 के 3.7 बिलियन यूएस डॉलर के मुकाबले मामूली तौर पर कम रहा। दूसरी ओर, भारत का आयात 2021 में 9.3 बिलियन यूएस डॉलर का था। उसकी तुलना में 2022 में आयात बढ़कर 34.5 बिलियन यूएस डॉलर का हो गया। इसका मुख्य कारण 2022 में रूस से कच्चे तेल का अधिक आयात रहा। इससे भारत के आयात में विशेष रूप से वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप, व्यापार घाटा 2021 के 5.6 बिलियन यूएस डॉलर की

ईएईयू वाणिज्यिक वस्तु व्यापार

देश	निर्यात (मिलियन यूएस डॉलर)				आयात (मिलियन यूएस डॉलर)				व्यापार संतुलन (मिलियन यूएस डॉलर)			
	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022	2019	2020	2021	2022
आर्मेनिया	38.2	45.2	55.3	50.2	1.8	75.3	121.8	100.0	36.3	-30.1	-66.5	-49.9
बेलारूस	56.1	58.8	71.0	42.9	207.6	206.3	365.9	180.8	-151.5	-147.5	-294.9	-137.9
कजाकिस्तान	193.7	225.8	207.2	435.2	1593.6	1294.9	530.4	246.8	-1399.9	-1069.1	-323.2	188.3
किर्गिस्तान	29.1	36.8	31.7	47.6	2.1	5.3	1.5	3.6	27.4	34.7	26.4	46.1
रुस	2975.0	2560.4	3326.8	2912.3	6238.2	5936.6	8252.2	34003.6	-3263.2	-3376.3	-4925.3	-31091.3
ईएईयू	**3292.1**	**2908.3**	**3710.7**	**3488.1**	**8043.3**	**7518.4**	**9271.7**	**34534.9**	**-4751.2**	**-4591.4**	**-5579.6**	**-31046.7**

स्रोत : आईटीसी ट्रेड मैप

तुलना में बढ़कर 31 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। हालांकि, रूस के साथ भारत के आयात में 312% से अधिक की वृद्धि हुई। इसके परिणामस्वरूप इसी अवधि के दौरान व्यापार घाटा भी अधिक रहा।

ईएईयू को 2022 में भारत के प्रमुख निर्यात में फार्मासूटिकल उत्पाद (15.3%) शामिल रहे। उसके बाद इलेक्ट्रिकल मशीनरी (12.7%), जैविक रसायन (8.6%), मशीनरी (8.5%), लौह और इस्पात (4.6%) और कॉफी, चाय, मेट और मसाले (4%) शामिल हैं। ईएईयू से 2022 में भारत के प्रमुख आयातों में खनिज ईंधन और तेल (82.8%), उर्वरक (7.1%), मोती और कीमती रत्न (3.6%), पशु और वनस्पति वसा (2.2%) तथा लौह और इस्पात (0.8%) शामिल रहे।

ईएईयू में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और भारत के साथ द्विपक्षीय निवेश

ईएईयू में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) प्रवाह 2013 में 66.9 बिलियन यूएस डॉलर का था। यह 2022 में घटकर (-) 9.7 बिलियन यूएस डॉलर का रहा। अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट-2023 के अनुसार, रूस-यूक्रेन संघर्ष का रूस से आने-जाने वाले निवेश प्रवाह पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा है। इस कारण कई मौजूदा निवेश परियोजनाओं को रोकना और घोषित परियोजनाओं को रद्द करना पड़ा है। वर्ष 2021 में रूस वैश्विक स्तर पर 9वां सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्तकर्ता था। तब वहां 38.2 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई आया था। हालांकि, संघर्ष के परिणामस्वरूप, 2022 में कई बड़ी कंपनियों द्वारा विनिवेश किए जाने के कारण एफडीआई प्रवाह गिरकर (-) 19 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। दूसरी ओर, कज़ाकिस्तान में एफडीआई प्रवाह लगभग दोगुना होकर 6.1 बिलियन यूएस डॉलर हो गया है। वहां निष्कर्षण उद्योगों में वृद्धि हुई। विशेष तौर पर नीदरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में संचालित बहुराष्ट्रीय उद्यमों (एमएनई) से इस उद्योग में निवेश आया। यह मुख्यतः निष्कर्षण उद्योगों में हुए उच्च लाभ से बढ़ी हुई आय का पुनर्निवेश ही था। ईएईयू से एफडीआई बाहर भी गया। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2013 में 73.2 बिलियन यूएस डॉलर का एफडीआई इस क्षेत्र से बाहर गया था। यह 2022 में घटकर 8.4 बिलियन यूएस डॉलर हो गया। अधिकांश एफडीआई रूस से बाहर गया। जबकि कज़ाकिस्तान और बेलारूस कई रूसी कंपनियों के लिए पसंदीदा निवेश स्थल बन गए।

एफडीआई मार्केट्स डेटाबेस के अनुसार, 2013-2022 के दौरान कोयला, तेल और गैस क्षेत्र ईएईयू में पूंजी निवेश के प्रमुख प्राप्तकर्ता रहे। इन क्षेत्रों में 224.7 बिलियन यूएस डॉलर के कुल प्राप्त निवेश 28% हिस्सा आया। इसके बाद क्रमशः खाद्य और पेय पदार्थ (13%) और रसायन (6%) का स्थान रहा। ईएईयू में 2013-2022 की अवधि के दौरान अमेरिका सबसे बड़ा निवेशक रहा। उसने ईएईयू में आए कुल एफडीआई में 24.3% का योगदान दिया। अन्य प्रमुख निवेशकों में चीन (ईएईयू द्वारा प्राप्त कुल एफडीआई का 20.9% हिस्सा), फ्रांस (5.5%), जर्मनी (5.1%) और नीदरलैंड (3.4%) का नंबर रहा। जहां तक निवेश प्राप्त करने वाले देशों का सवाल है, तो रूस ने 2013-2022 के दौरान ईएईयू देशों में सर्वाधिक 62.4% हिस्सेदारी के साथ सबसे ज्यादा पूंजी निवेश प्राप्त किया। इसके बाद कज़ाकिस्तान (31.7%), बेलारूस (3%), आर्मेनिया (2.1%) और किर्गिज़स्तान (0.8%) का स्थान रहा। जनवरी 2013 से दिसंबर 2022 के दौरान, ईएईयू में भारत का कुल अनुमानित पूंजी निवेश 1.9 बिलियन यूएस डॉलर रहा। इससे भारत इस क्षेत्र में 24वां सबसे बड़ा निवेशक देश बन गया। भारत ने ईएईयू में मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस, फार्मासूटिकल्स एवं खाद्य तथा पेय उद्योगों में निवेश किया है। भारत से ईएईयू में अधिकतम निवेश 2015 में हुआ। उस वर्ष भारत ने कज़ाकिस्तान में 1 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश किया। रूस को 2013-2022 के दौरान भारत से 753 मिलियन यूएस डॉलर मिले। जबकि बेलारूस को भारत से 1 मिलियन यूएस डॉलर प्राप्त हुए।

ईएईयू के पूंजी निवेश के लिए 2013 से 2022 के दौरान, मिस्र सबसे बड़ा गंतव्य स्थल बनकर उभरा। उसे इस दौरान कुल 112 बिलियन यूएस डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ। इसमें 27.5% हिस्सेदारी ईएईयू की रही। इसके बाद इस मामले में इराक (10.1%), जॉर्डन (9%), उज़्बेकिस्तान (8.3%), वियतनाम (5.6%) और चीन (4.3%) आदि का स्थान रहा। भारत में ईएईयू द्वारा किया गया कुल पूंजी निवेश 1.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा। यह 2013 से 2022 के बीच ईएईयू द्वारा किए गए कुल निवेश का 1.5% है। ईएईयू के लिए भारत 10वां सबसे बड़ा निवेश प्राप्तकर्ता था। जबकि इस क्षेत्र में भारत के निवेश स्रोत केवल रूस और बेलारूस ही रहे। रूस ने इस क्षेत्र से भारत में किए गए कुल निवेश में 97.8% की हिस्सेदारी दर्ज कराई। वर्ष 2013 से 2022 की अवधि में रूस और बेलारूस से भारत में मुख्य रूप से कोयला, तेल और गैस (प्राप्त कुल निवेश का 51%) क्षेत्र में निवेश आया। इसके बाद एयरोस्पेस (10%) और धातु (7%) क्षेत्र का स्थान रहा। ■

भारत-ओमान संबंधों को बढ़ावा देना

– **सारा जॉय,** *मुख्य प्रबंधक*
अल्फिया अंसारी, *उप प्रबंधक*

भारत और ओमान संबंधों में हाल के समय में नए आयाम देखने को मिले हैं। दोनों अर्थव्यवस्थाएं आर्थिक साझेदारी को और बढ़ाने के लिए व्यापक समझौते पर हस्ताक्षर करने को उत्सुक हैं। लिहाजा अब समय है कि भारत-ओमान अपने व्यापार और निवेश संबंधों को मजबूती से आगे बढ़ाएं और आपसी संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाएं। भारत और ओमान के पारस्परिक हित में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिहाज से निम्नलिखित नीतिगत पहलें मददगार हो सकती हैं।

चिकित्सा पर्यटन को प्रोत्साहन देना

भारत, विशेष रूप से ओमान के लोगों के लिए भी, चिकित्सा पर्यटन का शीर्ष स्थल बन चुका है। क्योंकि यहां सस्ती, उच्च गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं। भारत की उन्नत चिकित्सा अवसंरचना के साथ ही हृदय रोग तथा कैंसर के इलाज जैसी विशिष्टताओं में विशेषज्ञता चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। पश्चिमी देशों की तुलना में यहां की तमाम तरीके की चिकित्सा प्रक्रियाएं किफायती हैं। यह भी इस ट्रेंड में एक प्रमुख कारक है। भारत आयुर्वेद और योग जैसे पारंपरिक उपचारों सहित समग्रता में मरीजों की देखभाल पर जोर देता है। यह भी ओमान से आने वाले मरीजों को पसंद आता है। ऐसे में, इस ट्रेंड को और बढ़ावा देने के लिए दोनों सरकारें स्वास्थ्य के क्षेत्र में सहयोग बढ़ा सकती हैं। इस हेतु वीजा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित कर सकती हैं और सांस्कृतिक संवेदनशीलता सुनिश्चित कर सकती हैं। संस्थानों के बीच सहयोग सेवाओं को बढ़ाया जा सकता है। इस तरह का सर्वसमावेशी पैकेज प्रस्तुत किया जा सकता है, जिससे ओमानी चिकित्सा पर्यटकों के लिए भारत एक आदर्श विकल्प बन जाए। इन संबंधों को मजबूत करने से न केवल चिकित्सा सेवा उद्योग को लाभ हो सकता है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान और आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिल सकता है।

हरित हाइड्रोजन में सहयोग

ओमान आज हरित हाइड्रोजन को स्थायी ईंधन के रूप में बढ़ावा देने के अभियान का अगुआ है। और वर्ष 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना है। ओमान अक्षय ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधनों की प्रचुरता और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्धता ओमान को कम उत्सर्जन वाले ईंधन की ओर हो रहे वैश्विक बदलाव में एक प्रमुख किरदार बनाती है। ऐसे में, भारत भी हरित हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों में अपनी विशेषज्ञता के साथ, अक्षय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के लिए ओमान से सहयोग बढ़ा सकता है। यह साझेदारी ओमान की अर्थव्यवस्था में विविधता ला सकती है। कार्बन उत्सर्जन को कम कर सकती है और तकनीकी नवाचार को बढ़ा सकती है। दोनों देशों के संयुक्त प्रयास उत्पादन तक सीमित न रहकर हरित हाइड्रोजन के भंडारण और उपयोग के लिए बुनियादी ढांचे के विकास तक हो सकते हैं। इससे दोनों देश हरित हाइड्रोजन बाजार में अग्रणी बन जाएंगे। दोनों देशों के सहयोगात्मक प्रयास पर्यावरणीय चिंताओं को दूर कर सकते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकते हैं और वैश्विक पहलों के अनुरूप स्थायी ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा दे सकते हैं।

खाद्य एवं कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग

भारत और ओमान आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए खाद्य और मत्स्य पालन क्षेत्र में सहयोग कर सकते हैं। भारत का कृषि प्रौद्योगिकी क्षेत्र लगभग 24 बिलियन यूएस डॉलर का है। यह ओमान के कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और प्रशिक्षण का अवसर प्रस्तुत करता है। दोनों देशों की संयुक्त अनुसंधान परियोजनाएं और साझेदारियां संधारणीय पद्धतियों तथा रोग प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। ओमान का मत्स्य पालन क्षेत्र वहां की अर्थव्यवस्था में महत्त्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्र भी मछली प्रसंस्करण और जलीय कृषि में दोनों देशों के बीच सहयोग के अवसर उपलब्ध कराता है। ओमान `मत्स्यपालन और जलीय कृषि संकल्पना–2040' को साकार करने पर काम कर रहा है। इस संकल्पना का लक्ष्य इस क्षेत्र को संपोषी उद्योग में बदलना है। इस लिहाज से भी भारत के साथ सहयोग अंतरराष्ट्रीय बाजारों में ओमान की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ा सकता है। भारत को भी विविध समुद्री खाद्य पदार्थों का स्रोत उपलब्ध करा सकता है। इस तरह के सहयोगात्मक प्रयास दोनों देशों को आर्थिक रूप से लाभान्वित कर सकते हैं और क्षेत्र में नवाचार बढ़ा सकते हैं।

ओमान की चक्रीय अर्थव्यवस्था से सीखना

ओमान चक्रीय अर्थव्यवस्था (सर्कुलर इकॉनॉमी) की ओर बढ़ रहा है, जिससे अपशिष्ट को कम किया जा सके और सस्टैनबिलिटी को प्रोत्साहन दिया जा सके। ओमान की `विज्ञान–2040' में संपोषी विकास प्रमुख घटक है। यह घटक जीडीपी वृद्धि, रोजगार, एफडीआई और ऊर्जा खपत पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। ओमान कुशल अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसने अब तक 67 रीसाइक्लिंग सुविधाएं स्थापित की हैं, जहां 31% कचरे की रीसाइक्लिंग की जा रही है। पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए ओमान अक्षय ऊर्जा एकीकरण की भी संभावना तलाश रहा है। भारत ने भी चक्रीय अर्थव्यवस्था के सहयोग देने के लिए नियम बनाए हैं। इनमें प्लास्टिक और ई-कचरा प्रबंधन के नियम भी शामिल हैं। लिहाजा, ओमान के साथ सहयोग भारत को अपशिष्ट प्रबंधन, रीसाइक्लिंग और नवीकरणीय ऊर्जा में बहुमूल्य इनसाइट्स और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण प्रदान कर सकता है। यह साझेदारी संधारणीय प्रयासों को बढ़ा सकती है। नवाचार को बढ़ावा दे सकती है। साथ ही, वृतीय अर्थव्यवस्था के सिद्धांतों के अनुरूप नए आर्थिक अवसर पैदा कर सकती है।

डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग

भारत और ओमान डिजिटल प्रौद्योगिकी में सहयोग कर सकते हैं, जिससे कि क्रॉसबार्डर डेटा मूवमेंट को सुगम बनाया जा सके और फिनटेक (वित्त प्रौद्योगिकी) में साझेदारी को बढ़ाया जा सके। डेटा सुरक्षा व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखना महत्त्वपूर्ण है। इससे संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रखते हुए गैर-व्यक्तिगत और अज्ञात निजी डेटा का आदान-प्रदान सुगम होता है। भारत और ओमान डेटा एडीकेसी अग्रीमेंट कर सकते हैं, जिससे यह डेटा प्रवाह सुगम हो सकता है, साथ ही इससे पारस्परिक उपयुक्तता सुनिश्चित होगी और नागरिकों की निजता की रक्षा भी होगी। इसके अतिरिक्त, भारत के यूपीआई और सिंगापुर के PayNow के साथ जोड़ने के सफल प्रयास को भी दोहराया जा सकता है। भारत की भुगतान प्रणालियों को ओमान की प्रणालियों के साथ जोड़ने से सीमा पार ट्रांज़ैक्शन सुव्यवस्थित किया जा सकता है। इससे वे तेज और अधिक किफायती बन सकती हैं। यह सहयोग दोनों देशों के बीच नवाचार और निवेश को बढ़ा सकता है। भुगतान और भेजी जाने वाली रकम की सहज, आसान आवाजाही भी सुनिश्चित कर सकता है।

सहयोगात्मक लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर

लॉजिस्टिकल बुनियादी ढांचे को अगर बेहतर किया जाए तो ओमान में भारत के निर्यात को काफी बढ़ावा मिल सकता है। दोनों देश आर्थिक तरक्की के लिए पर्यटन और लॉजिस्टिक्स जैसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रहे हैं। ओमान की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति और महत्त्वपूर्ण व्यापार मार्गों से लगे गहरे पानी के उसके बंदरगाह उसे एक आकर्षक साझीदार बनाते हैं। दोनों के बीच सहयोगात्मक प्रयास ट्रांज़ैक्शन लागत को कम कर सकते हैं। आपसी संपर्क (कनेक्टिविटी) में सुधार कर सकते हैं। इससे दोनों अर्थव्यवस्थाओं को लाभ होगा। उदाहरण के लिए, दुक्म बंदरगाह और `दुक़्म विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण' बुनियादी ढांचे के विकास के लिए विदेशी निवेश तलाश रहे हैं। वहीं भारत अपनी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ बुनियादी ढांचे के विकास पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इससे दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग के अवसर बनते हैं। लॉजिस्टिक संबंधों को मजबूत करने से व्यापार प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित किया जा सकता है। व्यापार मार्गों में विविधता लाई जा सकती है। इस तरह सुचारू व्यापार सुविधा मिल सकती है। इससे अंततः आर्थिक विकास को तो बढ़ावा मिलेगा ही, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध भी मजबूत होंगे। ■

इंडिया एक्ज़िम बैंक की ऋण-व्यवस्थाएं

सौजन्य : **लाइन्स ऑफ क्रेडिट ग्रुप**

भारत सरकार ने अन्य के साथ-साथ विशेष रूप से विकासशील देशों के साथ भारत के व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय वर्ष 2003-04 के आम बजट के जरिए भारत विकास पहल (आईडीआई) की शुरुआत की थी। इसे बाद में भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना (आइडियाज़) नाम दिया गया। इस योजना का उद्देश्य विदेश में भारत के रणनीतिक, राजनैतिक और आर्थिक हित को बढ़ावा देना है। इस संबंध में भारत विकासशील देशों के साथ क्षमता विकास और कौशल हस्तांतरण, व्यापार तथा बुनियादी ढांचे के विकास के जरिए अपने विकास अनुभव साझा करता है और इस तरह स्वयं को उभरती आर्थिक शक्ति और निवेशक देश और विकासशील देशों के लिए एक सहभागी के रूप में स्थापित करता है। बैंक पॉलिसी संस्था के रूप में इस `आइडियाज़' योजना के तहत दूसरे देशों को प्रदत्त ऋण व्यवस्थाओं के लिए एक वित्तपोषण के माध्यम का काम करता है।

नवीनतम `आइडियाज़' दिशानिर्देश संशोधित किए गए हैं। ये 31 मार्च, 2022 से प्रभावी हैं। संशोधित `आइडियाज़' दिशानिर्देशों के तहत, भारत सरकार की रियायती वित्तपोषण योजना (सीएफएस) को इस योजना में मिला दिया गया है। इसमें भारत सरकार रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण विदेशी बुनियादी ढांचागत परियोजनाओं के लिए बोली लगाने वाली भारतीय इकाईयों को सहयोग करने के लिए ऋण सहायता लेने वाली किसी भी सरकार या सरकार के स्वामित्त्व या नियंत्रण वाली इकाई को रियायती वित्तपोषण प्रदान करती है। यह वित्त तब प्रदान किया जाता है, जब उक्त भारतीय इकाई ऐसी किसी विदेशी इकाई द्वारा टेंडर की गई परियोजना के निष्पादन का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर लेती है । इस वित्तपोषण के लिए पात्र परियोजना का रणनीतिक महत्त्व भारत सरकार द्वारा मामले वार आधार पर तय किया जाता है।

भारत सरकार द्वारा संप्रभु सरकारों या उनकी नामित एजेंसियों को दी जाने वाली ऋण व्यवस्थाएं वित्तीय वर्ष 2003-04 से भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) द्वारा प्रदान की जा रही हैं। ऋण-व्यवस्थाएं भारतीय निर्यातकों को नए भौगोलिक क्षेत्रों में प्रवेश करने या मौजूदा निर्यात बाजारों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में सहायक हैं और वह भी विदेशी आयातक से बिना किसी भुगतान जोखिम के। बैंक भारतीय निर्यातकों के लिए किसी बाजार में प्रवेश के एक प्रभावी माध्यम के साथ-साथ बाजार विविधीकरण के साधन के रूप में ऋण-व्यवस्थाएं प्रदान करने पर विशेष जोर देता है। ये ऋण-व्यवस्थाएं बड़े पैमाने पर जटिल परियोजनाओं (भारत से परियोजना निर्यात) के लिए सहभागी देशों को प्रदान की जा रही हैं।

इंडिया एक्ज़िम बैंक विदेशी वित्तीय संस्थानों, क्षेत्रीय विकास बैंकों, संप्रभु सरकारों और विदेशों की सरकार द्वारा नामित अन्य संस्थाओं को ऋण-व्यवस्था (एलओसी) प्रदान करता है। ताकि उन देशों के खरीदार भारत से विकासात्मक और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं, उपकरणों, वस्तुओं और सेवाओं का आयात कर सकें। हालांकि ऋण-व्यवस्थाएं किसे दी जानी हैं, उनकी राशि क्या होगी और नियम व शर्तें क्या होंगी, इसका निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। तथापि, ये ऋण-व्यवस्थाएं इंडिया एक्ज़िम बैंक द्वारा प्रदान की जाती हैं और बैंक इनके परिचालन तथा निगरानी के माध्यम के रूप में काम करता है।

ऋण-व्यवस्था के अंतर्गत, इंडिया एक्ज़िम बैंक भारतीय निर्यातकों को एफओबी/सीएफआर/सीआईएफ/सीआईपी आधार पर अनुबंध मूल्य की 100% प्रतिपूर्ति करता है। इन ऋणों के तहत कवर किए गए अनुबंधों के मूल्य की कम से कम 75% वस्तुएं और सेवाएं (परामर्श सेवाओं सहित) भारत से ली जानी चाहिए। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत को उभरते बाजारों में परियोजना निष्पादन क्षमताओं का प्रदर्शन करने में सक्षम बनाया है। ऋण-व्यवस्थाओं ने हाल के वर्षों में, विशेष रूप से अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिनिया और सीआईएस के विकासशील देशों में काफी गति हासिल करने में मदद की है। ऋण-व्यवस्थाओं ने भारत के राजनीतिक, रणनीतिक और वाणिज्यिक हितों को बढ़ावा देने के अलावा लाभार्थी देशों में भारत के लिए अपेक्षित राजनीतिक सद्भाव बनाने में मदद की है। ऋण-व्यवस्था भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत के साथ-साथ प्राप्तकर्ता विकासशील देशों में अवसंरचना के विकास और क्षमता विकास में योगदान करने की इच्छा को प्रदर्शित करने में मदद करती है। ऋण-व्यवस्थाएं प्राप्तकर्ता देश के बाजारों में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात में भी मदद करती है, जिसमें भारत की उपस्थिति नहीं है। भारतीय निर्यातकों को शिपिंग दस्तावेजों के निगोशिएशन / सेवाओं के प्रावधान (अनुमोदित भुगतान शर्तों के अनुसार) के एवज में पात्र मूल्य का भुगतान मिल जाता है और वे खरीदार या खरीदार देश के जोखिम से चिंतामुक्त रहते हैं।

बैंक ने पास 21 मार्च, 2024 तक 293 लाइन्स ऑफ क्रेडिड की हैं, जो अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ओशिआनिया और सीआईएस में 68 से अधिक देशों को कवर करती हैं। इसमें 27.30 बिलियन यूएस डॉलर से अधिक की ऋण प्रतिबद्धताएं हैं, जो भारत के निर्यात के वित्तपोषण के लिए उपलब्ध हैं। इस प्रकार ऋण-व्यवस्थाएं भारत की परियोजनाओं, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने और सुविधा प्रदान करने के लिए प्रभावी माध्यम है।

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया संपर्क कीजिए :

श्री दीपक कुजूर,
सहायक महाप्रबंधक,
भारतीय निर्यात-आयात बैंक, ऑफिस ब्लॉक, टॉवर 1, 7वीं मंज़िल,
रिंग रोड के नजदीक, किदवई नगर (पूर्व)
नई दिल्ली-110023, फोनः (011) 24607700
ईमेलः eximloc@eximbankindia.in

दास्तान-ए-कामयाबी

मोज़ाम्बिक में पहला सौर पीवी पैनल संयंत्र - देश को ऊर्जान्वित करने और बदलाव लाने की दिशा में बड़ी छलांग

इंडिया एक्ज़िम बैंक ने मोज़ाम्बिक सरकार को भारत सरकार समर्थित 13 मिलियन यूएस डॉलर की ऋण व्यवस्था प्रदान की। यह सहायता मोज़ाम्बिक में टर्नकी आधार पर प्रति वर्ष 5 मेगावाट के सौर फोटो-वोल्टिक मॉड्यूल विनिर्माण संयंत्र की स्थापना के लिए है।

इंडिया एक्ज़िम बैंक के माध्यम से भारत सरकार की ऋण- व्यवस्था की मदद से, मोज़ाम्बिक के ऊर्जा कोष - एफयूएनएई - के स्वामित्त्व वाली फैक्ट्री ने सौर फोटो-वोल्टिक (पीवी) पैनलों को किफायती दर पर उपलब्ध कराया है। इससे अब यह देश आयात पर अधिक खर्च करने वाले दौर से आगे बढ़ते हुए पड़ोसी देशों को पीवी पैनलों की आपूर्ति कर विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। यही नहीं, यहां हवा की गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उसमें सूक्ष्म पर्टिकुलेट मैटर (पीएम 2.5) 2010 में 23.56 माइक्रोन प्रति घन मीटर थे। ये घटकर 2017 तक 21.30 माइक्रोन प्रति घन मीटर हो गए हैं। ■

तिमाही गतिविधियां

सौजन्य : **कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन ग्रुप**

व्यापार सुगमीकरण और सूचना पोर्टल, एक्ज़िम मित्र 2.0 के विकास के लिए साथ आए एक्ज़िम बैंक और एमएसएमई मंत्रालय

देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की सहायता के लिए भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्ज़िम बैंक) और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय मिलकर काम कर रहे हैं। इसके लिए दोनों के बीच एक सहमति ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू एक्ज़िम बैंक द्वारा भारतीय निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र के निर्यातकों के लिए व्यापार वित्त और संबंधित सूचनाओं को सुगम बनाने के लिए बनाए गए एक्ज़िम मित्र पोर्टल के रीलॉन्च के लिए किया गया है, जिसे एक्ज़िम मित्र 2.0 के नाम से जाना जाएगा। इस एमओयू पर एमएसएमई मंत्रालय में अपर सचिव और विकास आयुक्त, डॉ. रजनीश तथा एक्ज़िम बैंक की प्रबंध निदेशक, सुश्री हर्षा बंगारी ने हस्ताक्षर किए। इस दौरान, भारत सरकार के माननीय केंद्रीय एमएसएमई मंत्री, श्री नारायण राणे और उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय एमएसएमई, खादी और ग्रामोद्योग, रेशम उद्योग, हथकरघा और वस्त्र मंत्री, श्री राकेश सचान विशेष रूप से उपस्थित रहे। यह एमओयू ग्रेटर नोएडा में 14 फरवरी, 2024 को प्रौद्योगिकी केंद्रों के उद्घाटन समारोह के दौरान किया गया।

इस सहयोग से एक्ज़िम बैंक का व्यापार सुगमीकरण और सूचना पोर्टल `एक्ज़िम मित्र' और सुदृढ़ होगा, जहां निर्यात बाजार में संभावनाएं तलाशने वाली भारतीय कंपनियों को व्यापार संबंधी सूचनाओं, हैंडहोल्डिंग और सहयोग सेवाएं एक क्लिक पर उपलब्ध हैं। एक्ज़िम बैंक अब इसे एक्ज़िम मित्र 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप के रूप में पुन- विकसित करने की प्रक्रिया में है। दूसरी ओर, वैश्विक वैल्यू चेन में भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की प्रतिभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा विदेशी बाजारों पर निर्यात से जुड़े डेटा की सेंट्रल नॉलेज रिपोज़िटरी के रूप में `ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस सिस्टम (जीएमआईएस)' तैयार किया जा रहा है। एक्ज़िम मित्र 2.0 और जीएमआईएस के साझा उद्देश्य और एकरूपता को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई मंत्रालय और एक्ज़िम बैंक मिलकर एकीकृत पोर्टल तैयार कर रहे हैं। इस सहयोग से एमएसएमई मंत्रालय के उद्यम रजिस्ट्रेशन डेटा तक एक्ज़िम बैंक की पहुंच बन सकेगी और इसका उपयोग कर रजिस्टर्ड उद्यम उपयोक्ताओं को एक्ज़िम मित्र 2.0 पोर्टल और मोबाइल ऐप पर उनकी आवश्यकतानुसार सामग्री उपलब्ध कराई जा सकेगी। इस सहयोग से एक्ज़िम मित्र 2.0 के जरिए भावी निर्यातकों को उनकी जरूरत के मुताबिक सामग्री और बेहतर संसाधन उपलब्ध कराए जा सकेंगे।

एक्ज़िम मित्र 2.0 के जरिए व्यापार से जुड़ी सूचनाएं और डेटा सुलभ होगा और उपयोक्ताओं को बेहतर एक्सेस तथा अबाधित सेवाएं मिलेंगी। इसके अलावा, `निर्यात के शुरुआती कदम" पर वीडियो सीरीज़ के साथ-साथ पॉडकास्ट, ब्लॉग और जानकारीपरक वीडियो जैसी मल्टीमीडिया सामग्री भी उपलब्ध कराई जाएगी और उपयोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार माध्यम चुनकर जानकारी हासिल कर सकेंगे। इस पोर्टल पर एक चैटबॉट भी होगा, जो उपयोक्ताओं को निर्यातकों के सवालों के त्वरित उत्तर देगा और उन्हें तुरंत संबंधित सूचना तक पहुंचाएगा। इसकी पहुंच को बढ़ाने के उद्देश्य से यह पूरी सामग्री दूसरी भारतीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराई जाएगी।

इंडिया एक्ज़िम बैंक का इन-हाउस एक्सपोर्ट लीडिंग इंडेक्स

भारतीय निर्यात-आयात बैंक (इंडिया एक्ज़िम बैंक) ने वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही के लिए भारत के निर्यात पूर्वानुमान जारी कर दिए हैं। वित्तीय वर्ष 2024 की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च) में, भारत के कुल मर्चैंडाइज़ निर्यात 118.2 बिलियन यूएस डॉलर और गैर-तेल निर्यात 95 बिलियन यूएस डॉलर के रहने का पूर्वानुमान है। मर्चैंडाइज निर्यात में जहां 2.96% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का पूर्वानुमान है, तो वहीं गैर-तेल निर्यात में 4.55% की वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का अनुमान है। यह सकारात्मक वृद्धि वर्ष की प्रथम दो तिमाहियों में रही ऋणात्मक वृद्धि के बाद दर्ज की जा रही है। भारत के निर्यात में यह सकारात्मक वृद्धि, भारत के जीडीपी वृद्धि परिदृश्य में सुधार तथा बढ़ती वैश्विक मांग के बीच मौद्रिक सख्ती में वैश्विक नरमी के कारण हो सकती है। तथापि, यह परिदृश्य अन्य के साथ-साथ, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं के संबंध में अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक झटकों, मध्य पूर्व संकट के चलते तीव्र होते लाल सागर संकट और गहराते भू-आर्थिक फ्रैग्मेंटेशन जैसे जोखिमों पर निर्भर करता है।

इस पूर्वानुमान के साथ, पूर्ण वित्तीय वर्ष 2024 के लिए भारत का कुल मर्चैंडाइज़ निर्यात 435.3 बिलियन यूएस डॉलर का रहने की उम्मीद है। जबकि गैर-तेल निर्यात के गत वर्ष के स्तर पर बने रहने की संभावना है। तथापि, वर्ष के दौरान तेल निर्यातों में मंदी बने रहने के आसार हैं और वित्तीय वर्ष 2023 की तुलना में 12.5 बिलियन यूएस डॉलर कम रहने का पूर्वानुमान है। ■

विभिन्न देशों का आर्थिक परिदृश्य

सौजन्यः **शोध एवं विश्लेषण समूह**

कनाडा

कनाडा दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी और जी-7 के सदस्य देशों में सबसे छोटी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ यह अत्यधिक एकीकृत है, जो कनाडा का सबसे बड़ा व्यावसायिक भागीदार भी है। कनाडा की अर्थव्यवस्था वैसे तो सेवा-आधारित है, लेकिन यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातकों में से भी एक है। वर्ष 2023 में बैंक ऑफ कनाडा (बीओसी) द्वारा सख्त मौद्रिक नीति अपनाने के कारण कनाडा में आर्थिक गतिविधियां (1.1%) प्रभावित हुई। इससे 2024 में भी कनाडा की विकास दर 1.2% का अनुमान कम (1.2%) आंका गया। इसके बावजूद, कनाडा की अर्थव्यवस्था को सरकारी खर्च में वृद्धि से लाभ होने की उम्मीद है। सरकार ने मुद्रास्फीति राहत में सुधार के लिए सरकारी सहायता प्राप्त योजनाओं में खर्च बढ़ाया है। इसके बाद भी आवास और इसके उप-क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का दबाव अभी बना हुआ है। मगर वर्ष 2024 के अंत तक, अनुमान है कि मुद्रास्फीति बीओसी की ओर से निर्धारित 2% के लक्ष्य पर आ जाएगी। उपभोक्ता कीमतें धीरे-धीरे कम हो रही हैं। उन्हें 2023 की उच्च आधार दरों से मदद मिल रही है। कनाडाई डॉलर ने 2010 के दशक के उत्तरोत्तर वर्षों में अपना आधार खो दिया था। लेकिन अंतरराष्ट्रीय ऋण बाजारों तक देश की उत्कृष्ट पहुंच के बलबूते अब अगले दो वर्षों में इसमें सुधार की उम्मीद है। वर्ष 2025-28 में स्थानीय मुद्रा- कनाडाई डॉलर की औसत विनिमय दर 1 यूएस डॉलर के मुकाबले 1.26 रहने का अनुमान है। वह भी सीमित अस्थिरता के साथ। जबकि माल आयात की मजबूत मांग और तेल की कीमतें कमजोर होने से 2025-28 की पूरी अवधि में चालू खाता घाटा रहने की संभावना है।

स्विटज़रलैंड

स्विस अर्थव्यवस्था अत्यधिक खुली है। विकसित और सेवा-उन्मुख भी है। इसमें सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के दो-तिहाई से अधिक भागीदारी निर्यात की रहती है। वर्ष 2024 में आर्थिक गतिविधि ठंडी रहने का अनुमान है। ऐसे में वास्तविक जीडीपी में केवल 0.9% की वृद्धि ही अनुमानित है। वर्ष 2023 के दौरान भी जीडीपी में 0.8% की धीमी वृद्धि दर्ज हुई थी। घरेलू मांग और निश्चित निवेश पर अल्प अवधि में उच्च ब्याज दरों के कारण बाधा बनी रहने की आशंका है। जबकि बाह्य परिस्थितियां निर्यात की मांग को और कम कर सकती हैं। यह स्विटज़रलैंड के निर्यात-उन्मुख उद्योगों में निरंतर कमजोरी का कारण बन सकता है। वर्ष 2024 में औसत उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति भी धीमी होकर 1.4% तक रहने का अनुमान है। यह धीमापन कमजोर आयातित मुद्रास्फीति दबाव को दर्शाता है। स्विस बैंक हाल के ऐतिहासिक मानकों से मजबूत बना हुआ है। इसे दो स्थितियों से समर्थन मिल रहा है। पहली- देश की सेफ-हेवन की स्थिति और दूसरी- यह उम्मीद कि स्विस नेशनल बैंक अल्पावधि में दरों को अपने मौजूदा स्तर पर बनाए रखेगा। स्विट्ज़रलैंड का चालू-खाता अधिशेष वैश्विक संदर्भ में आम तौर पर बड़ा है। यह उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों के लिए मूल्यवान एक मजबूत विनिर्माण क्षेत्र के कारण पर्याप्त व्यापार अधिशेष पर आधारित है। वर्ष 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के 10% के अनुमानित चालू-खाता अधिशेष के बाद, 2024-25 में इसके कम होने की उम्मीद है। इसका कारण यह है कि व्यापार अधिशेष भी कम होने का अनुमान है। यह स्थिति एक मजबूत आयात वृद्धि को दर्शाती है।

बोलीविया

बोलीविया की अर्थव्यवस्था में 2023 के 2.2% के मुकाबले 2024 में 1.9% तक गिरावट का अनुमान है। इसके दो कारण हैं। पहला- निजी उपभोग वृद्धि में नरमी और दूसरा- निर्यात में संकुचन। बोलीविया वस्तुओं का निवल आयातक है। इस कारण वह वैश्विक मुद्रास्फीति के दबाव का सामना कर सकता है। इससे औसतन मुद्रास्फीति 2024 में 3.5% तक बढ़ने का अनुमान है। जबकि 2023 में यह 2.6% थी। चालू खाता घाटा भी 2023 में सकल घरेलू उत्पाद के अनुमानित 3.1% के आस-पास था। यह 2024 में बढ़कर सकल घरेलू उत्पाद का 4.3% और 2025 में 4.5% तक पहुंच सकता है। इसका मुख्य कारण यह है कि अर्जेंटीना ने प्राकृतिक गैस के आयात में कटौती की है। बोलीविया में 2025 में आम चुनाव भी हैं। इस कारण केंद्रीय बैंक द्वारा 2024 में विनिमय दर (बोलिवियानो 6.91 : 1 यूएस डॉलर) में बदलाव की संभावना नहीं है। चालू खाते के उच्च घाटे के साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार भी सीमित है। वर्ष 2023 में यह केवल 1.5 महीने के आयात को संभालने लायक स्थिति तक पहुंच गया है। इसके अलावा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी बाहर जा रहा है। बाहरी पूंजी बाजारों तक सरकार की पहुंच नहीं है। इस सबसे सरकार की साख खराब हुई है। राजनैतिक गतिरोध ने आधिकारिक बाहरी फंडिंग तक समय पर पहुंच सुनिश्चित करने की सरकार की क्षमता को बाधित किया है और कमजोर आर्थिक स्थितियों को बढ़ा दिया है। कुल मिलाकर, मध्यम अवधि में बोलीविया का आर्थिक भविष्य अनिश्चित बना हुआ है।

चीन

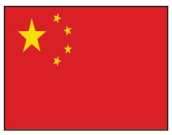

चीन में आर्थिक मंदी का दबाव जारी रह सकता है। 2024 में अनुमानित वृद्धि दर 4.7% की रह सकती है। जबकि 2023 के लिए यह दर 5.2% थी। कोविड-19 संकट के बाद चीन के रियल एस्टेट बाजार में गिरावट देखी जा रही है। चीन की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों में शुमार "एवरग्रांड" के ढह जाने के बाद वित्तपोषण के तरीकों पर सरकार द्वारा नियामक कार्रवाई से निवेशकों का भरोसा हिल गया है। इसके अलावा, महंगाई कम करने का दबाव भी चीनी अर्थव्यवस्था पर हावी है। वस्तुओं की कीमतों में अपेक्षित वृद्धि का अनुमान है, खास तौर पर सुअर के मांस की कीमतें बढ़ सकती हैं। इससे 2024 में मुद्रास्फीति की दर 1% तक रह सकती है। अमेरिका में सख्त मौद्रिक नीति के सिलसिले के अंत की संभावना है। इससे 2022-23 के कमजोरी के दौर के बाद अब 2024 में चीनी मुद्रा की विनिमय दर चीनी युआन 7.1 : 1 यूएस डॉलर पर स्थिर रह सकती है। वैश्विक भंडार घट रहा है, जिससे चीनी वस्तुओं की मांग बढ़ रही है। इस कारण 2024 में सकल घरेलू उत्पाद के 1.5% के अनुमानित चालू खाते अधिशेष के साथ चीन फिर से एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बन सकता है। निजी खपत, सार्वजनिक निवेश और निर्यातों की पुनर्प्राप्ति से 2024 के दौरान अर्थव्यवस्था में सुधार की स्थिति बरकरार रखने में मदद मिल सकती है। कामकाजी युवाओं की आबादी में कमी और मिश्रित उत्पादकता दृष्टिकोण जैसे जनसांख्यिकीय मुद्दे मध्यम अवधि में चुनौती पेश करते हैं। ■

मुद्रा की प्रवृत्तियां

सौजन्य : **ट्रेजरी एंड अकाउंट्स ग्रुप**

यूएस डॉलर

$ फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में आक्रामक बढ़ोतरी के बाद आखिरकार उपभोक्ता कीमतें कम होने लगीं। इससे बीते साल डॉलर में लगभग 3% की गिरावट आई। इसके अलावा, मंदी के जोखिमों के बारे में चिंताएं, जापान में नकारात्मक दरों का दौर खत्म होने, तथा बिटकॉइन और कमोडिटी की कीमतों में वृद्धि का भी इस मुद्रा पर असर पड़ा।

डॉलर पटरी पर है और सकारात्मक रुख पर कारोबार कर रहा है। उसे इन अटकलों से समर्थन मिल रहा है कि फेडरल रिजर्व अभी लंबे समय तक उच्च ब्याज दरों के सिलसिले को बनाए रख सकता है। इसलिए कि अमेरिका में मुद्रास्फीति उच्च स्तर पर बनी हुई है। यूक्रेन और गाजा में युद्ध जारी हैं। यूरोप से चीन तक विकास की गति धीमी है। साथ ही कई चुनाव होने हैं, जो दुनिया की 40% से अधिक आबादी के नेतृत्व का निर्धारण करने वाले हैं। इससे `सुरक्षित-पनाहगाह' संपत्तियों की मांग इस साल भी बनी रह सकती है। इसके अलावा, संभावना यह भी है कि वर्ष 2008 के बाद से पहली बार केंद्रीय बैंक ब्याज दरों में सबसे समकालिक कटौती शुरू करने वाले हैं। इससे डॉलर को मौजूदा उछाल में मदद मिलेगी।

यूएस डॉलर और भारतीय रुपये की विनिमय दरों में बहुत ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं आया। चालू तिमाही में यह दर 83.35 और 82.64 के बीच रुपया रही। 20 मार्च, 2024 को एक डॉलर के मुकाबले 83.1675 पर बंद हुआ।

इंडोनेशियाई रुपिया

Rp बैंक इंडोनेशिया (बीआई) द्वारा अगस्त 2022 से अक्टूबर 2023 के बीच ब्याज दरों में कुल 250 आधार अंकों की बढ़ोतरी की गई। इस फैसले के बाद, इंडोनेशिया की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 2023 के मध्य से ही केंद्रीय बैंक की लक्षित सीमा के भीतर बनी हुई है। हाल ही में हुई नीतिगत बैठक में, इंडोनेशिया के केंद्रीय बैंक ने रुपिया को समर्थन देने के लिए धन जुटाने की लागत को पांच साल के उच्चतम स्तर 6% पर अपरिवर्तित रखा है। इसलिए कि नीति निर्माताओं ने अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बेंचमार्क ब्याज दर में कटौती की आवश्यकता के बिना ही ऋण तक पहुंच को आसान बनाने का विकल्प चुना। लिहाजा, विस्तारित दर पर इस रोक से रुपिया को मदद मिलेगी, जो इस साल अब तक डॉलर के मुकाबले लगभग 2% फिसल गया है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों को लेकर अनिश्चितता भी उभरते बाजार की मुद्राओं पर भारी पड़ रही है। इनमें से अधिकांश मुद्राएं अमेरिकी डॉलर के मुकाबले कमजोर हुई हैं। हालांकि, रुपिया ने कई क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है।

इस महीने की शुरुआत में, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और बैंक इंडोनेशिया (बीआई) ने मुंबई में एक सहमति पत्र (एमओयू) पर दस्खत किए हैं। इसमें सीमा पार लेनदेन के लिए स्थानीय मुद्राओं, जैसे- भारतीय रुपया (आईएनआर) और इंडोनेशियाई रुपिया (आईडीआर), के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए रूपरेखा बनाने पर सहमति दी गई है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर आक्रमण करने के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए, उन्हें देखते हुए कई अन्य देशों ने आपसी व्यापार के लिए अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता घटाने के ऐसे ही रास्ते तलाशे हैं।

यूएस डॉलर/ आईडीआर विनिमय दर 20 मार्च 2024 को एक डॉलर के मुकाबले 15,710 आईडीआर पर बंद हुई।

क्यूबन पेसो

₱ क्यूबा ऊर्जा और आर्थिक संकट में फंसा हुआ है। यह संकट कोविड-19 के बाद से और गहराया है। कम्युनिस्ट शासन वाले क्यूबा में ऊर्जा की कमी इतनी ज्यादा है कि अधिक मांग वाले समय में सार्वजनिक स्थलों की बिजली तक बंद करनी पड़ जाती है। वास्तव में यह महत्त्वपूर्ण मुद्रा वर्षों से इसी तरह जारी है। हाल के महीनों में ईंधन की कमी के कारण स्थिति और खराब हुई है।

क्यूबा ने 1994 में दोहरी मुद्रा प्रणाली लागू की। उसके तहत मौजूदा क्यूबन पेसो (सीयूपी) के साथ-साथ क्यूबन कन्वर्टिबल (परिवर्तनीय) पेसो (सीयूसी) भी चलन में लाया गया था। हालांकि तीन दशक तक दोनों मुद्राओं के साथ-साथ संचालन के बाद अब क्यूबा के राष्ट्रीय पेसो (सीयूपी) और इसके परिवर्तनीय पेसो (सीयूसी) को एकीकृत कर दिया गया। इससे क्यूबा का परिवर्तनीय पेसो तो खत्म हुआ ही, सरकारी उद्यमों के लिए 1 सीयूपी/यूएसडी दर भी समाप्त हो गई। अब क्यूबा में क्यूबन पेसो ही एकमात्र वैध मुद्रा है। वहां अमेरिकी डॉलर (यूएसडी) के मुकाबले सीयूपी की विनिमय दर का आकलन कर उसे एक डॉलर के मुकाबले 24 पेसो पर निश्चित किया गया है। हालांकि आधिकारिक एकीकरण के बावजूद अनौपचारिक विनिमय दरें भी अस्तित्व में हैं, जो क्यूबा की अर्थव्यवस्था के भीतर में मौजूद विकृतियों को दर्शाती हैं। अनौपचारिक दर, वर्तमान में एक यूएस डॉलर के मुकाबले 300 पेसो से ऊपर कारोबार कर रही है। आधिकारिक विनिमय दरों की तुलना में अक्सर इसी अनौपचारिक दर को क्यूबा पेसो के वास्तविक मूल्य के बेहतर प्रतिबिंब के रूप में देखा जाता है।

मिस्र का पाउंड

E£ 2011 की क्रांति के बाद से मिस्र, वर्तमान में अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। कमजोर मुद्रा, उच्च मुद्रास्फीति, बाहर जाती पूंजी और बढ़ते कर्ज के बोझ ने मिलकर देश की अर्थव्यवस्था पर जबरदस्त दबाव डाला है। लाल सागर क्षेत्र में अशांति और स्वेज नहर से मिलने वाले राजस्व में गिरावट ने इस स्थिति को और खराब किया है। इससे मिस्र के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी बहुत दबाव पड़ा है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ मिस्र ने हाल ही में एक समझौता किया है। मौजूदा चुनौतियों के बीच अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों में यह एक महत्त्वपूर्ण कदम है। आईएमएफ के साथ 8 बिलियन यूएस डॉलर का करार हुआ है। साथ ही, पर्यावरणीय सस्टैनेबिलिटी संधारणीयता के लिए 1.2 बिलियन यूएस डॉलर का अतिरिक्त ऋण भी मिलेगा। इससे मिस्र को बहुत मौके की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है।

मिस्र के केंद्रीय बैंक द्वारा ब्याज दरों में उल्लेखनीय वृद्धि के फैसले से रातों-रात ऋण दर 28.25% और जमा दर 27.25% तक पहुंच गई हैं। इससे मिस्र के पाउंड (ईजीपी) में रिकॉर्ड गिरावट आई है। यह गिरावट यूएस डॉलर के मुकाबले 50 के आस-पास है। वास्तविक अवमूल्यन और ब्याज दर में भारी बढ़ोतरी से पहले, केंद्रीय बैंक ने लगभग एक साल तक मुद्रा को डॉलर के मुकाबले 31 पाउंड से कम के स्तर पर बनाए रखा था।

यूएस डॉलर/ईजीपी की विनिमय दर 20 मार्च 2024 को एक डॉलर के मुकाबले 46.96 रही। ■

एक्ज़िम मित्र

सौजन्य: **एक्ज़िम मित्र समूह**

भारत के अन्तरराष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाने और भारतीय उद्यमियों के बीच व्यापार वित्त, ऋण बीमा और व्यापार से जुड़ी अन्य जानकारियों के प्रसार की विषमता को दूर करने के लिए इंडिया एक्ज़िम बैंक ने एक पोर्टल तैयार किया है। इसके मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। निर्यात के लिए ऋण उपलब्धता के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना और व्यापार से संबंधित सूचनाएं प्रदान करना। एक्ज़िम मित्र के जरिए ऐसे प्रयास करना, जिनसे भारतीय उद्यमियों की अन्तरराष्ट्रीय व्यापार से जुड़ी जिज्ञासाओं का समाधान हो। इनमें से कुछ को नीचे दिया गया है:

भारतीय निर्यातों के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम के बारे में जानकारी

बाजार विकास सहायता (एमडीए) कार्यक्रम भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय द्वारा भारतीय निर्यातकों की मदद के लिए प्रस्तुत एक वित्तीय सहायता योजना है। जिससे वे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में अपने उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा दे सकें। विदेशों में नए बाजारों की खोज और उन्हें विकसित करने में भारतीय निर्यातकों को सहायता पहुंचाना इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। इसमें निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी) को सहायता प्रदान करना भी शामिल है, ताकि वे विशिष्ट उत्पादों और वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन गतिविधियां शुरू कर सकें। इसके अलावा, अनुमोदित संगठनों और व्यापार निकायों को मदद करना भी एक अहम उद्देश्य है। जिससे वे अपने सदस्यों के लिए अनेकानेक अभिनव निर्यात प्रोत्साहन पहल कर सकें। इसके अतिरिक्त, लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई (एलएसी), अफ्रीका, सीआईएस (स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रमंडल), और आसियान+2 (दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संघ+2) जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में फोकस निर्यात प्रोत्साहन कार्यक्रमों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना भी है।

ऐसी निर्यातक कंपनियां जिनके एफओबी (फ्री ऑन बोर्ड) निर्यातों का मूल्य पिछले वर्ष 15 करोड़ रुपये तक रहा है, वे इस कार्यक्रम के जरिए लाभ ले सकती हैं। वे व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और व्यापार प्रतिनिधिमंडलों में भाग लेने के लिए मदद ले सकती हैं। साथ ही, ईपीसी और व्यापार निकाय भी अपने सदस्यों के उत्पादों और सेवाओं के लिए प्रोत्साहन गतिविधियां चलाने के उद्देश्य से अनुदान प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं। बाजार विकास सहायता कार्यक्रम वाणिज्य मंत्रालय की सक्रिय और जारी पहल है। वाणिज्य मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कोई भी इस संबंध में नवीनतम जानकारी और आवेदन संबंधी दिशानिर्देश प्राप्त कर सकता है। वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है :

https://commerce.gov.in/about-us/divisions/export-services-division/export-and-arket-development-assistance-emda/

प्रवेश बिल (बीओई) क्या है और हाई-सी सेल्स में बीओई की जिम्मेदारी कौन लेता है?

प्रवेश बिल यानी बिल ऑफ एंट्री (बीओई) एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है। इसका उपयोग किसी देश में वस्तुओं के आयात के लिए सीमा शुल्क निकासी प्रक्रियाओं में किया जाता है। सीमा शुल्क अधिकारियों के लिए इसमें अनिवार्य रूप से वस्तुओं से जुड़ा पूरा विवरण दर्ज होता है। जैसे- मात्रा, मूल्य तथा किस देश से वस्तु भेजी गई है, आदि।

हाई-सी सेल्स के तहत समुद्र में परिवहन के दौरान ही किसी भी देश की समुद्री सीमा से बाहर रहते हुए वस्तुओं के स्वामित्त्व का स्थानांतरण कर दिया जाता है। हालांकि, जब अंतिम खरीदार (आयातक) अपने देश में वस्तुएं लाता है, तो उसे उनके लिए प्रवेश बिल जमा कराना ही पड़ता है। इस तरह के ज्यादातर मामलों में, वह अंतिम खरीदार जो अपने देश में सीमा शुल्क के माध्यम से वस्तुओं की निकासी कराना चाहता है, उसी की जिम्मेदारी है कि वह प्रवेश बिल जमा कराए। वही खरीदार सभी तरह के सीमा शुल्क और करों (जैसे- जीएसटी यानी भारत में लागू वस्तु एवं सेवा कर) के भुगतान के लिए भी उत्तरदायी होता है। इस उत्तरदायित्त्व में अपवाद सिर्फ तब हो सकते हैं, जब विक्रेता और खरीदार के बीच इससे संबंधित कोई विशिष्ट समझौता हुआ हो। जैसे- कुछ मामलों में, प्रारंभिक विक्रेता अंतिम खरीदार की ओर से सीमा शुल्क निकासी प्रक्रिया को संभालने के लिए सहमत हो सकता है। ऐसा इसलिए किया जा सकता है, ताकि विक्रेता और समुद्री यात्रा के दौरान ही वस्तुएं खरीदने वाले पहले खरीदार के बीच जो बिक्री मूल्य तय हुआ है, वह अंतिम आयातक को पता न चले। ऐसी स्थिति में, अंतिम खरीदार के लिए विक्रेता एक एजेंट के रूप में कार्य करता है। वही जरूरी दस्तावेज के साथ प्रवेश बिल दाखिल करता है।

प्रवेश बिल सटीक होना चाहिए। इसमें वस्तुओं का सही मूल्य और विवरण दर्ज होना चाहिए। हाई-सी सेल से संबंधित लेनदेन के मामलों में सीमा शुल्क अधिकारी बीओई के अतिरिक्त भी अन्य दस्तावेज मांग सकते हैं। ऐसे में सीमा शुल्क से जुड़े कामकाज कराने वाले लोगों (ब्रोकर्स) से संपर्क कर उनसे इस बाबत विशिष्ट आवश्यकताओं, नियमों, आदि के बारे में परामर्श लेना महत्त्वपूर्ण होता है।

कंटेनर खो जाने की स्थिति में सीमा शुल्क की वसूली और एमईआईएस डेबिट को वापस कराने की जानकारी

जब कोई कंटेनर `एक बार अच्छा' घोषित कर दिया जाए और निर्यात के दौरान खो जाए, तो भुगतान किए गए सीमा शुल्क को फिर प्राप्त करना तथा डेबिट को आपके एमईआईएस (भारत से वस्तु निर्यात योजना) रिवॉर्ड स्क्रिप में वापस लाना महत्त्वपूर्ण होता है। सीमा शुल्क अधिनियम-1962 में प्रावधान है कि अगर निर्यातित वस्तुएं गंतव्य बंदरगाह तक भौतिक रूप से नहीं पहुंची हैं और उनसे संबंधित सीमा शुल्क का भुगतान हो चुका है, तो उस शुल्क की वापसी का दावा किया जा सकता है। इसके लिए नुकसान की पुष्टि करने वाले सभी तरह के दस्तावेज की आवश्यकता होगी। जैसे- लदान बिल (बीओएल), शिपिंग लाइन से हुए नुकसान की घोषणा करने वाला घोषणा-पत्रक, नुकसान की पुष्टि करने वाले बीमा दावे से संबंधित दस्तावेज, पुलिस शिकायत (यदि लागू हो तो), आदि। गंतव्य बंदरगाह पर वस्तुओं के पहुंचने की अपेक्षित तिथि से लगाकर अगले छह महीने के भीतर कोई कभी भी इस तरह की वापसी दावा दायर कर सकता है।

आपके एमईआईएस रिवॉर्ड स्क्रिप में डेबिट को वापस करने की प्रक्रिया डीजीएफटी (विदेश व्यापार महानिदेशालय) के विशिष्ट दिशा-निर्देशों पर निर्भर करती है। व्यक्ति को डीजीएफटी के पास एक आवेदन दाखिल करना होगा। इसमें कंटेनर के नुकसान संबंधी पूरी विस्तृत जानकारी देनी होगी। साथ ही, सीमा शुल्क वापसी का दावा दायर किए जाने का प्रमाण भी देना होगा। डीजीएफटी द्वारा इसकी जांच कराई जाएगी। जांच में मामला सही पाए जाने पर वहां से अनुमोदन के बाद ही डेबिट को एमईआईएस स्क्रिप में वापस करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।

आंकड़ों में भारतीय अर्थव्यवस्था

सौजन्य: **शोध एवं विश्लेषण समूह**

वस्तु व्यापार

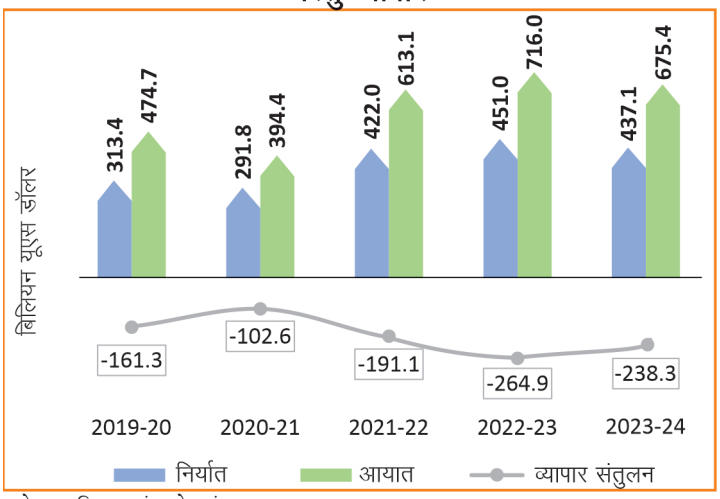

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सेवा व्यापार

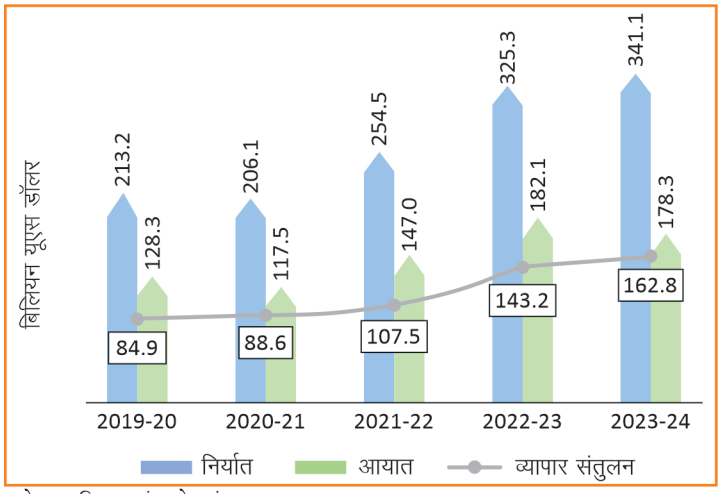

स्रोत: वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

चालू खाता घाटा

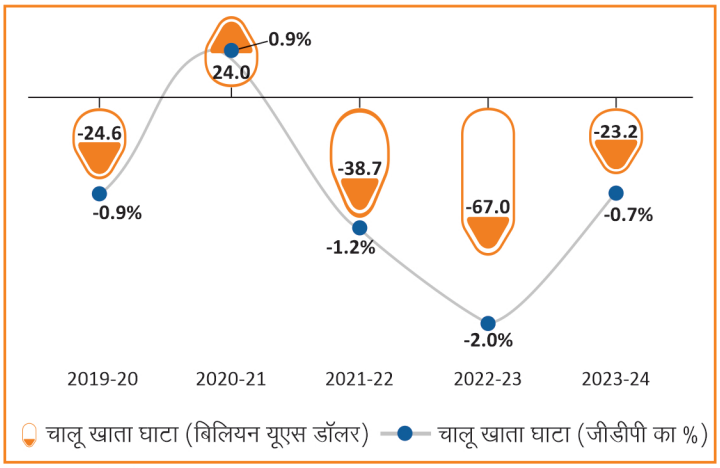

स्रोत: आरबीआई

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

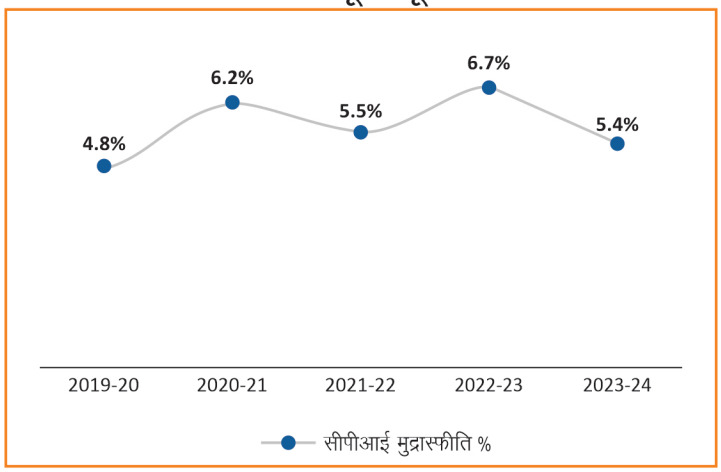

स्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा निवेश का प्रवाह

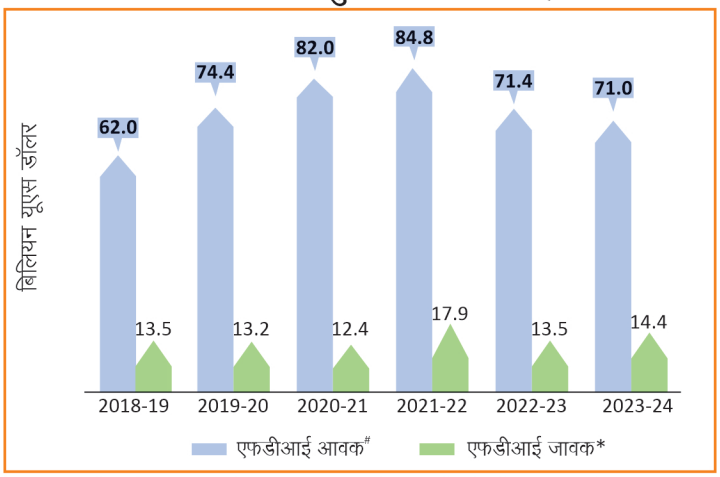

*नोट: *एफडीआई जावक वास्तविक आंकड़े दर्शाते हैं और इसमें इक्विटी, ऋण, इन्वोक की गारंटियां शामिल हैं।*
#एफडीआई आवक में इक्विटी, पुनर्निवेश आय और अन्य पूंजी शामिल है।
स्रोत: आरबीआई और वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

क्षेत्रवार उत्पादन

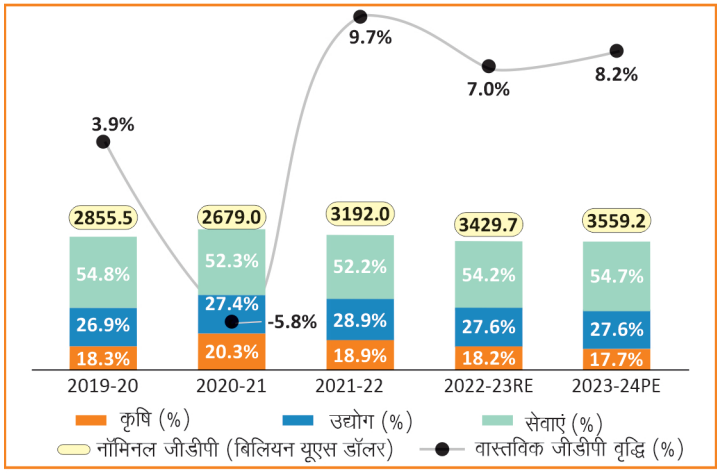

नोट: पीले रंग के आंकड़े नॉमिनल जीडीपी (बिलियन यूएस डॉलर) को दर्शाते है ;
आरई– संशोधित अनुमान ; पीई– अंतिम अनुमान
स्रोत: अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थान फाइनेंस एंड सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार